नई दिल्ली
बुधवार
09 सितंबर 2026
वर्षः 13, अंकः 06
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर...पेज-05

DELHIN/2014/58158

सत्य निकेतन हादसाः घायलों का हाल जानने एम्स....पेज-02

एक नजर

चेक बाउंस मामला : राजपाल यादव को पांच करोड़ रुपये जमा करने पर ही मिलेगी सरेंडर से छूट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 5 करोड़ रुपये जमा करने पर ही सरेंडर करने की छूट का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजपाल यादव से कहा कि 9 सितंबर तक उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि अगर राजपाल यादव 9 सितंबर तक पांच करोड़ रुपये जमा नहीं करते हैं तो उन्हें जेल जाना होगा। इसके पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को राजपाल यादव को तीन महीने की कैद की सजा सुनाई थी। राजपाल यादव को कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। हालांकि जून 2024 में उच्च न्यायालय ने सजा को निलंबित कर दिया था।उच्च न्यायालय ने कहा था कि राजपाल यादव आदतन अपराधी नहीं हैं, इसलिए उनकी सजा निलंबित की जाती है। दरअसल, कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस केस में दोषी करार देने के बाद राजपाल यादव पर 1 करोड़ 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। कड़कड़डूमा कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की पत्नी राधा पर भी 10 लाख रुपये प्रति केस जुर्माना लगाया था। दोनों को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में यह सजा सुनाई गई थी। शिकायतकर्ता मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने कोर्ट को बताया था कि राजपाल ने अप्रैल 2010 में फिल्म अता पता लापता पूरी करने के लिए कंपनी से मदद मांगी थी। 30 मई 2010 में दोनों के बीच करार हुआ और उन्होंने राजपाल यादव की कंपनी को 5 करोड़ का लोन दे दिया। करार के मुताबिक राजपाल को ब्याज सहित आठ करोड़ रुपये लौटाने थे लेकिन वह पहली बार ये रकम नहीं लौटा सके। उसके बाद दोनों के बीच तीन बार करार का रिनिवल हुआ।

दिल्ली में एक संगीतकार की हत्या पर राजनीति नहीं होनी चाहिएः रिजिजू

नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में हाल ही में एक संगीतकार की कथित हत्या के मामले में केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए में कहा कि इस दुखद घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि पूरा ध्यान त्वरित और सख्त कार्रवाई पर होना चाहिए। रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'वे भी भारतीय हैं। पूर्वोत्तर के लोग भी भारतीय हैं। यह राजनीति करने का मामला नहीं है बल्कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।' उन्होंने बताया कि ढाबे के कर्मचारियों और खाना पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय के बीच देर रात किसी बात को लेकर हुए विवाद के दौरान यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। रात के समय अचानक हुए इस झगड़े का किसी को पता नहीं चल सका लेकिन मृतक के बेटे द्वारा पीसीआर कॉल किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाई। मंत्री ने बताया कि संदिग्धों के मौके से भागने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने उन्हें बहुत कम समय में गिरफ्तार कर लिया है। जब उन्होंने पुलिस से चार्जशीट दाखिल करने को लेकर सवाल किया, तो उन्हें बताया गया कि घटना के आठ से नौ दिनों के भीतर ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त सजा मिल सके। राहुल गांधी द्वारा इस घटना को लेकर सरकार को घेरने पर आपत्ति जताते हुए रिजिजू ने सवाल किया कि ऐसी दुखद घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी को क्यों घसीटा जाता है।

एआई युग के लिए युवाओं को तैयार करना जरूरी, भारत को बनाना है वैश्विक महाशक्तिः नरेंद्र मोदी

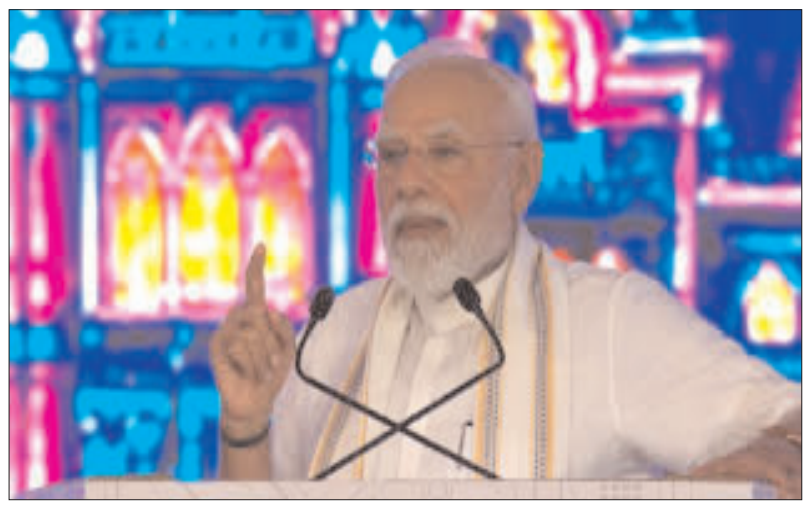

वडोदरा,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में दुनिया के सामने महाशक्ति बनना है तो देश को इसके लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि एआई में दक्ष युवाओं की जरूरत केवल सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि कृषि, स्वास्थ्य, विनिर्माण और रोबोटिक्स सहित हर क्षेत्र में एआई नए समाधान और रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को एआई के लिए तैयार करने की दिशा में बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है।

'नमो फॉर विकसित भारत' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का युवा विशेष कौशल हासिल कर उसका इस्तेमाल एआई के साथ मिलाकर नई तकनीक और समाधान विकसित कर सकता है। कोई युवा कृषि के लिए एआई समाधान तैयार कर सकता है, स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीक विकसित कर सकता है, विनिर्माण की उत्पादकता बढ़ा सकता है या अपना रोबोटिक्स स्टार्टअप शुरू कर सकता है। इसलिए भारत और दुनिया के उद्योगों की जरूरतों को समझने तथा एआई का इस्तेमाल करने वाले युवाओं को तैयार करना जरूरी है। मोदी ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और वैश्विक जरूरतों के साथ शिक्षा और सीखने के तरीके भी बदल रहे हैं। पहले केवल डिग्री पर जोर था, अब कौशल का महत्व भी उतना ही बढ़ गया है। युवाओं के कौशल को लगातार उन्नत करना जरूरी है और इसी उद्देश्य से सरकार शिक्षा नीति तथा शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में बदलाव कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की मेहनत की कमाई बचाने के लिए सरकार छात्रों को देश के श्रेष्ठ शिक्षकों से मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए ऐसी कनेक्टिविटी जरूरी है, जो सुगम होने के साथ समय की जरूरत के अनुरूप तेज भी हो। उन्होंने कहा कि वडोदरा गतिशक्ति विश्वविद्यालय का शहर है और आज यहां डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अंतिम कड़ियां भी जुड़ गई हैं। इसके साथ ही देश में 2,800 किलोमीटर से अधिक लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा हो गया है, जो 21वीं सदी के भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 2004 में विचार शुरू हुआ था और 2006 में विशेष कंपनी बनाई गई, लेकिन 2014 तक फाइलें ही एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहीं। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि इन फाइलों को भी कोई 'डेडिकेटेड कॉरिडोर' नसीब नहीं हुआ। फाइलें अटकती, लटकती और भटकती रहीं। मोदी ने कहा कि 2014 के बाद उनकी सरकार ने इस परियोजना को गति दी और आज 2,800 किलोमीटर का काम पूरा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अब देश के व्यापार और कारोबार की मुख्य आधारशिला बन रहे हैं। इन पर प्रतिदिन 430 से अधिक मालगाड़ियां चल रही हैं। पहले मालगाड़ी को 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब साढ़े छह घंटे लगते थे, जबकि अब यही दूरी आधे से भी कम समय में पूरी हो रही है। जहां ट्रक से सामान पहुंचाने में सामान्यत: करीब 30 घंटे लगते हैं, वहीं फ्रेट कॉरिडोर से यह दूरी 10-12 घंटे में पूरी हो जाती है। इससे ईंधन, समय और परिवहन लागत की बचत के साथ पर्यावरण को भी लाभ हुआ है। मोदी ने हाल में मुंबई के जेएनपीटी बंदरगाह से वडोदरा तक चली डबल-स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का उल्लेख करते हुए कहा कि एक बार में 250 से अधिक ट्रकों के बराबर सामान पहुंचाया गया। ट्रक कारोबार को लेकर उठाए जाने वाले सवालों पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि 'नाराज फूफा जी' पूछेंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा लेकिन अब इन 'फूफा जी' को भी काम मिल गया है। उन्होंने कहा कि फ्रेट कॉरिडोर के साथ रेल उन आदिवासी क्षेत्रों तक भी पहुंच रही है, जहां दशकों तक रेल संपर्क नहीं था। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऐसे क्षेत्रों को भी रेल से जोड़ा जा रहा है। मोदी ने कहा कि पहले बजट में एक-दो ट्रेनों की घोषणा होती थी और साल भर उसका ढोल पीटा जाता था, जबकि आज देश में लगातार नई ट्रेनें शुरू हो रही हैं। आज के कार्यक्रम में भी कई नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष रेल बजट पौने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जो 12 वर्ष पहले की तुलना में कई गुना अधिक है। रेलवे के आधुनिकीकरण पर हो रहा यह खर्च हजारों-हजार नए रोजगार भी पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद भारत ने करीब 50 हजार आधुनिक रेल कोच बनाए हैं। पिछली सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, 'पुरानी सरकार 10 साल में 50 हजार टॉयलेट नहीं बना सकी थी। विनिर्माण क्षेत्र का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि भारत अब 'चिप्स से शिप्स' तक विनिर्माण की नई गाथा लिख रहा है। देश में केवल अंतिम उत्पाद ही नहीं, बल्कि उसके घटकों और पूरी आपूर्ति श्रृंखला को भारत में विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है।

भाजपा के लिए सत्ता, संगठन, पद और प्रतिष्ठा का उद्देश्य केवल सेवा हैः मोदी

नवसारी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का हर कार्यकर्ता दिन-रात लोगों की सेवा के लिए पूरी ताकत से जुटा रहता है। भाजपा के लिए सत्ता, संगठन, पद और प्रतिष्ठा का उद्देश्य केवल सेवा है। नवसारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की पूरी मेहनत का एकमात्र उद्देश्य 140 करोड़ देशवासियों का कल्याण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलना उनके लिए हमेशा उत्साह और आनंद का अवसर होता है। उन्होंने कहा कि नवसारी आना उनके लिए विशेष खुशी का विषय है और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद उन्हें नई ऊर्जा देता है। मोदी ने अपने गुजरात के मुख्यमंत्रित्व काल के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने भीषण गर्मी के बीच गांव-गांव जाकर बेटियों की शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया था। उन दिनों कई गांवों में 24 घंटे बिजली तक उपलब्ध नहीं थी और 44 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में उन्होंने गांवों का दौरा कर अभिभावकों को बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि उस समय किया गया यह जमीनी काम न तो अखबारों में प्रकाशित हुआ और न ही टेलीविजन पर दिखाई दिया लेकिन वह पूरी निष्ठा के साथ हर साल गांवों में जाते रहे। मोदी ने कहा, "सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। समाज इतना उदार होता है कि वह सेवा का ऋण आशीर्वाद के रूप में लौटाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवसारी में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए शिविर लगाए गए हैं। कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण किट उपलब्ध कराने में समाज की भागीदारी हो रही है तथा क्षय रोग (टीबी) के मरीजों को भी पोषण सहायता दी जा रही है।

इसरो ने उन्नत उपग्रह ईओएस-05 का तीसरा और अंतिम कक्षा उन्नयन चरण सफलतापूर्वक पूरा किया

चेन्नई,एजेंसी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 'ईओएस-05' का तीसरा और अंतिम कक्षा उन्नयन(ऑर्बिट रेजिंग) चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस उपग्रह को गत शुक्रवार को श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी-एफ17 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। इसरो के अनुसार, ईओएस-05 की एपोजी (पृथ्वी से अधिकतम दूरी) को बढ़ाने की यह तीसरी प्रक्रिया 07 सितंबर रात 8:57 बजे सफलतापूर्वक पूरी की गई। इस दौरान उपग्रह में लगे लिक्विड एपोजी मोटर इंजन को 1,247 सेकंड के लिए प्रज्वलित किया गया। इस प्रक्रिया के बाद उपग्रह के सभी उपकरण पूरी तरह सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। इससे पहले, 2,367 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह को प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद 'सब-जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट' (सब-जीटीओ) में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। उपग्रह का पहला कक्षा उन्नयन चरण 5 सितंबर को पूरा किया गया था, जिसमें एलएएम इंजन को 5,406.4 सेकंड के लिए चलाया गया था। इसके बाद दो और चरण पूरे करके उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट (जीएसओ - 85.5 डिग्री ईस्ट ऑर्बिटल स्लॉट) की दिशा में बढ़ा दिया गया है। यह भारत के अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार है जब किसी तस्वीर लेने वाले उपग्रह को भू-समकालिक कक्षा से संचालित किया जा रहा है। अंतरिक्ष में भारत की 'दिव्य दृष्टि' माना जा रहा ईओएस-05 उपग्रह, हर पांच मिनट में चयनित क्षेत्रों तथा हर 30 मिनट में संपूर्ण भारतीय भूभाग की 42 मीटर रिज़ॉल्यूशन वाली स्पष्ट तस्वीरें भेजने में सक्षम है। यह उपग्रह वर्ष 2021 में असफल हुए जीआईसैट-1ए मिशन का स्थान लेगा और कृषि, पर्यावरण निगरानी, आपदा प्रबंधन तथा समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में देश की दूर संवेदन क्षमताओं को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा।

अगले साल मई में शुरू होगा बुलेट ट्रेन का परीक्षणः वैष्णव

वडोदरा,एजेंसी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बुलेट ट्रेन परियोजना काम तेजी से चल रहा है और अगले साल मई से जून के बीच भारत में बनी बुलेट ट्रेन का परीक्षण शुरू हो जायेगा। श्री वैष्णव ने मंगलवार को यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में बुलेट ट्रेन का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। बुलेट ट्रेन परियोजना का काम तेजी से चल रहा है और इस साल दिसंबर तक सूरत से वापी तक रेलखंड के निर्माण का कार्य पूरा हो जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प के तहत देश में बन रही बुलेट ट्रेन का पहला बॉडी फ्रेम गत रविवार को परीक्षण के लिए भेजा जा चुका है और अगले साल मई से जून के बीच भारत में बनी बुलेट ट्रेन का परीक्षण शुरू हो जायेगा। इसके दो से तीन महीने बाद श्री मोदी देश की पहली बुलेट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

कांग्रेस का आरोप, वैधानिक जिम्मेदारी से भाग रहा जनजातीय मंत्रालय

नई दिल्ली,एजेंसी। वन अधिकार कानून, 2006 (एफआरए) के तहत वन भूमि के डायवर्जन से पहले ग्राम सभा की भूमिका को लेकर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के हालिया रुख पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मंत्रालय कानून की गलत व्याख्या कर अपनी वैधानिक जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मंत्रालय पर 'मोदानी' समूह और अन्य खनन कंपनियों का दबाव है। रमेश ने मंगलवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा कि 31 अगस्त को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ऊर्जा मंत्रालय को बताया कि वन अधिकार कानून और उसके तहत बनाए गए नियमों में गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के डायवर्जन से पहले ग्रामसभा की सहमति से जुड़ा प्रावधान नहीं है। यह रुख मंत्रालय के अपने पुराने दिशा-निर्देशों और पूर्व में अपनाई गई कानूनी स्थिति के विपरीत है।

उन्होंने कहा कि 12 जुलाई 2012 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्यों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया था कि वन भूमि के डायवर्जन और वनवासी समुदायों से जुड़े मामलों में एफआरए की धारा-4 का अनुपालन जरूरी है। जनवरी 2018 में भी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी, जिसमें एफआरए अनुपालन की शर्त को वन स्वीकृति की प्रक्रिया के बाद के चरण में ले जाने की बात थी। रमेश ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय एफआरए के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। ऐसे में वह कानून के दायरे से खुद को अलग नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति कानून और उन समुदायों दोनों को कमजोर करने वाली है, जिनके अधिकारों की रक्षा के लिए यह कानून बनाया गया था।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 31 अगस्त को ऊर्जा मंत्रालय के एनएचपीसी डेस्क को भेजे कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि वन अधिकार कानून (एफआरए), 2006 और इसके तहत बनाए गए नियमों में स्टेज-2 वन स्वीकृति के लिए ग्राम सभा की सहमति लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामले उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। वह केवल उन जलविद्युत और सिंचाई परियोजनाओं की पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन (आरएंडआर) योजनाओं को मंजूरी देता है, जिनमें परियोजना से प्रभावित अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवार शामिल होते हैं।

भारत-चीन संबंध धीरे-धीरे सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैंः रणधीर जायसवाल

नई दिल्ली,एजेंसी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत-चीन संबंध धीरे-धीरे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने संबंधों को सामान्य बनाने में लोगों के बीच संपर्क को महत्वपूर्ण बताते हुए वीजा सुविधा को इसका प्रमुख हिस्सा बताया। भारत का कहना है कि दोनों देशों के बीच व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सीमा पर निरंतर शांति और स्थिरता आवश्यक है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 6 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश के वाचा और 7 सितंबर को चीन के दमाई में भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर पर पहली फ्लैग मीटिंग हुई। प्रवक्ता ने कहा, 'अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में क्रमशः बीजिंग और नई दिल्ली में हुई 'वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन' (डब्ल्युएमसीसी) की बैठकों में हुई चर्चाओं के आधार पर, वरिष्ठ सैन्य कमांडर-स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश के वाचा और 7 सितंबर को चीनी तरफ़ दमाई में आयोजित की गई। पश्चिमी सेक्टर में भी इसी तरह की व्यवस्था मौजूद है। उल्लेखनीय है कि भारत-चीन संबंधों में साल 2025 से धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिले हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू हुई, सीधी उड़ानों और चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा की सुविधा बहाल हुई तथा नाथू ला जैसे सीमा व्यापार मार्गों को दोबारा खोला गया।

सहारा जमाकर्ताओं को बड़ी राहत, रिफंड पोर्टल फिर शुरू

नई दिल्ली,एजेंसी। सहारा समूह की सहकारी समितियों में फंसे जमाकर्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) ने लंबित दावों के सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल बहाल कर दिया है। अब लंबित करीब 20 लाख आवेदनों की जांच और रिफंड प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। सहकारिता मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि अब तक 41,56,711 जमाकर्ताओं को कुल 9,267 करोड़ रुपये वापस किए जा चुके हैं। यह राशि सीधे जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा की गई है। पोर्टल बहाल होने के बाद शेष लंबित आवेदनों के सत्यापन और पात्र दावों के भुगतान का काम फिर गति पकड़ेगा। मंत्रालय के मुताबिक रिफंड की पूरी प्रक्रिया सुरक्षित, पारदर्शी, डिजिटल, कागजरहित और सत्यापन आधारित है। यह प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के 29 मार्च 2023 के आदेश के तहत संचालित की जा रही है। सरकार ने जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा और सहकारी क्षेत्र में लोगों का भरोसा मजबूत करने को प्राथमिकता दी है। मंत्रालय ने बताया कि नवंबर 2025 में सहारा सहकारी समितियों के परिसरों को कुछ मामलों के चलते सील किए जाने के बाद उनके कामकाज पर असर पड़ा था। इसके साथ ही हार्डवेयर और वार्षिक रखरखाव अनुबंध से जुड़े बकाये, जरूरी आईटी ढांचे और लाइसेंस के नवीनीकरण, मानव संसाधन तथा प्रशासनिक समस्याओं के कारण रिफंड दावों के सत्यापन और प्रसंस्करण की व्यवस्था बाधित हुई। सहकारिता मंत्रालय ने संबंधित हितधारकों और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों एवं प्राधिकरणों के साथ समन्वय कर इन अड़चनों को दूर किया। आवश्यक आईटी प्रणाली, बुनियादी ढांचे और लाइसेंस को बहाल करने के साथ प्रशासनिक एवं मानव संसाधन संबंधी समस्याओं का भी समाधान किया गया।

इसके बाद पोर्टल और उससे जुड़ी सत्यापन प्रणाली को फिर सक्रिय किया गया। रिफंड की प्रक्रिया सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के पात्र जमाकर्ताओं के लिए लागू है। इनमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता, और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद शामिल हैं। सरकार ने 18 जुलाई 2023 को सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया था। इसके जरिए जमाकर्ताओं को बिना कागजी प्रक्रिया के ऑनलाइन रिफंड का दावा करने की सुविधा दी गई। दावों का सत्यापन आधार ई-केवाईसी के माध्यम से किया जाता है। इसके तहत जमाकर्ता, सदस्यता और बैंक खाते से जुड़े विवरणों का संबंधित सहकारी समितियों के रिकॉर्ड से मिलान किया जाता है।

सत्य निकेतन हादसा: घायलों का हाल जानने एम्स पहुंचीं रेखा गुप्ता, हरसंभव सहायता का दिया भरोसा

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन पीजी हादसे में जख्मी छात्रों के परिजनों से यहां एम्स में मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के मुताबिक, गुप्ता ने परिजनों से छात्रों के स्वास्थ्य और उपचार की स्थिति की जानकारी ली और कहा कि सरकार घायल छात्रों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है और छात्रों के इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के चिकित्सकों से घायल छात्रों की स्थिति और उन्हें दिए जा रहे उपचार की विस्तृत जानकारी भी ली। सत्य निकेतन इलाके में छात्रों के पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास के तौर पर इस्तेमाल की जा रही इमारत रविवार को दोपहर करीब 1:30 बजे मरम्मत कार्य के दौरान ढह गई। मलबे से कुल 12 लोगों को बाहर निकाला गया जिनमें से सात लोगों की मौत हो गई जबकि पांच अन्य घायल हो गए। सीएमओ के बयान के अनुसार, चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री को बताया कि गंभीर रूप से घायल छात्रों के उपचार के लिए डॉक्टरों की टीम बनाई गई है जो लगातार उनकी स्थिति की निगरानी कर रही है। गुप्ता ने परिजनों को आश्वस्त किया कि उपचार से जुड़ी किसी भी आवश्यकता में सरकार हरसंभव मदद उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता घायल बच्चों का जीवन बचाना और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। गुप्ता ने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ लगातार संपर्क में है और उनकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने परिजनों को यह भी बताया कि सत्य निकेतन हादसे के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बयान में कहा गया है कि गुप्ता के सख्त निर्देशों पर दिल्ली में पीजी छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा तेज कर दी गई है और नगर निगम को इनका निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार, संबंधित जोन के अधिकारियों को भवन सुरक्षा, आवश्यक अनुमतियों, अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण-पत्र और अन्य निर्धारित मानकों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जोनल स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी इस पूरी कार्रवाई की निगरानी करेंगे। मुख्यमंत्री ने सत्य निकेतन में घटनास्थल के आसपास के भवनों में काम कर रहे श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नगर निगम को जन-सुरक्षा के हित में दुर्घटना स्थल के पास बने जर्जर भवनों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। बयान के मुताबिक, दिल्ली अग्निशमन सेवा के कर्मचारी व्यवस्थित तरीके से भवन के अंदर मौजूद छात्रों का सामान सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। इसमें सभी छात्रों और स्थानीय निवासियों से अधिकारियों का सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। पुलिस ने भवन ढहने के सिलसिले में इमारत की मालकिन 75 वर्षीय उर्मिला गुप्ता, वायु सेवा से सेवानिवृत्त 81 साल के उनके पति हरिराम गुप्ता और उनके बेटे महेश गुप्ता (52) को गिरफ्तार कर लिया है।

एनएसयूआई ने डीयू कुलपति पर कार्यक्रम में शामिल होने पर उठाए सवाल, इस्तीफे की मांग की

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह का सत्या निकेतन की घटना के बाद विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कुलपति से इस्तीफे की मांग की। एनएसयूआई के सदस्यों ने आर्ट्स फैकल्टी के पास आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन किया, जिसमें डीयू के कुलपति शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की असंवेदनशीलता पर सवाल उठाते हुए सत्या निकेतन त्रासदी से प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के प्रति जवाबदेही की मांग की।

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि जब सत्या निकेतन की त्रासदी के बाद छात्र और उनके परिवार असहनीय पीड़ा से गुजर रहे हैं, तब डीयू के कुलपति ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि कुलपति ने प्रभावित छात्रों के कितने परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है? उन्होंने कितने छात्रों से मिलकर उनका हाल जाना है? विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र आवास और हॉस्टल सुविधाओं के मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देने से क्यों बच रहा है? विनोद जाखड़ ने कहा कि सत्या निकेतन की त्रासदी ने एक बार फिर दिल्ली में छात्रों के लिए सुरक्षित और किफायती हॉस्टल की गंभीर कमी को उजागर किया है। जब विश्वविद्यालय पर्याप्त हॉस्टल सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहते हैं, तो छात्रों को असुरक्षित और उचित नियमन के अभाव वाले निजी आवासों पर निर्भर रहना पड़ता है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग की कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रों के लिए तत्काल सुरक्षित, किफायती और पर्याप्त हॉस्टल सुविधाओं का विस्तार करे तथा यह सुनिश्चित करे कि छात्रों के आवास निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करते हों। जाखड़ ने कहा कि जब डीयू प्रशासन छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, हॉस्टल संकट का समाधान नहीं कर सकता और इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा नहीं हो सकता, तो कुलपति को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। एनएसयूआई ने मांग की है कि सत्या निकेतन त्रासदी की परिस्थितियों की तत्काल जांच और जवाबदेही तय की जाए, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए सुरक्षित, किफायती और पर्याप्त हॉस्टल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, विश्वविद्यालय के हॉस्टलों और छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे निजी आवासों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराया जाए, डीयू प्रशासन त्रासदी से प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों से तत्काल संवाद करे और उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करे और छात्रों की सुरक्षा और आवास से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जाए।

सत्य निकेतन हादसे की जगह जैमर लगाने पर सौरभ भारद्वाज ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आआपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सत्य निकेतन में हुए इमारत हादसे के घटनास्थल पर मोबाइल जैमर लगाए जाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि जैमर लगाए जाने से हादसे में फंसे लोगों और मौके पर मौजूद लोगों के लिए मदद के लिए फोन करना मुश्किल हो गया। सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि सत्य निकेतन में पीजी छात्रों की इमारत के पास मोबाइल सिग्नल जाम करने का आदेश किसने दिया, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमारत ढहने जैसी घटनाओं में मलबे में फंसे लोग अक्सर मोबाइल फोन के जरिए अपने परिजनों या राहत एजेंसियों से संपर्क कर मदद मांगते हैं। आआपा नेता ने आरोप लगाया कि घटनास्थल पर जैमर लगाए जाने के कारण स्थानीय लोग एंबुलेंस या अन्य सहायता के लिए फोन नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि यदि मलबे में कोई व्यक्ति फंसा था और मोबाइल सिग्नल उपलब्ध नहीं था, तो उसकी स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से राहत एवं बचाव कार्य में कथित देरी को लेकर भी सवाल किया।

उन्होंने पूछा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम को घटनास्थल तक पहुंचने में दो से तीन घंटे क्यों लगे और सरकारी एंबुलेंस भी कथित तौर पर करीब दो घंटे की देरी से क्यों पहुंची। उन्होंने दावा किया कि घटना के बाद सबसे पहले ब्लिंकिट की एक निजी एंबुलेंस मौके पर पहुंची, जबकि प्रशासन की एंबुलेंस करीब दो घंटे बाद पहुंची।

सीसीटीवी फुटेज ने 14 साल बाद आरोपियों को इंसाफ दिलाया

नई दिल्ली,एजेंसी। कड़कड़डूमा कोर्ट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के 14 साल पुराने एक मुकदमे में फैसला सुनाते हुए भाटिया एसिड प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक हरिंदर भाटिया को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। इस लंबे कानूनी विवाद का रुख केवल एक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य यानी सीसीटीवी फुटेज के सामने आने से पूरी तरह पलट गया। इसी फुटेज ने इंसाफ दिलाया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुकृति झा की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। ईएसआईसी ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने मई 2007 से अगस्त 2010 की अवधि के दौरान कर्मचारियों की हाजिरी, वेतन रजिस्टर और खाता-बही जैसे वैधानिक दस्तावेज जांच के लिए अधिकारियों को नहीं दिखाए थे। 17, 23 और 30 मई 2012 को अधिकारियों ने कंपनी का दौरा किया, लेकिन रिकॉर्ड नहीं मिलने का दावा किया गया। इसके बाद विभाग ने वर्ष 2012 में ईएसआई कानून की धारा 85(जी) के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान ईएसआई के निरीक्षकों ने अदालत में बयान दिया कि जब किसी प्रतिष्ठान में दस्तावेज नहीं दिखाए जाते, तो उनका निरीक्षण दौरा 15 से 30 मिनट में ही खत्म हो जाता है।हालांकि, बचाव पक्ष द्वारा अदालत के समक्ष पेश की गई 30 मई 2012 की सीसीटीवी फुटेज ने विभागीय दावों की पोल खोल दी। सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट हुआ कि ईएसआई निरीक्षक दोपहर लगभग डेढ़ बजे कंपनी परिसर में दाखिल हुए थे और शाम को करीब पौने छह बजे बाहर निकले। अधिकारियों की इस साढ़े चार घंटे से अधिक लंबी मौजूदगी ने विभाग के आरोपों को पूरी तरह संदिग्ध बना दिया।

महापौर कार्यालय को नौवीं बार बम से उड़ाने की धमकी

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के महापौर कार्यालय को मंगलवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। यह नौवीं बार है जब महापौर कार्यालय को इस तरह की धमकी मिली है। सूचना मिलते ही महापौर कार्यालय ने तत्काल दिल्ली पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय कर दी गई। धमकी की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस एवं संबंधित सुरक्षा एजेंसियों ने महापौर कार्यालय परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा कर्मियों ने कार्यालय के संवेदनशील हिस्सों, प्रवेश एवं निकास द्वार तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की बारीकी से जांच की। पूरे परिसर का निरीक्षण कर निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया गया। महापौर कार्यालय के अनुसार, इससे पहले भी कार्यालय को आठ बार बम विस्फोट की धमकियां मिल चुकी हैं। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए महापौर कार्यालय ने पूर्व में दिल्ली पुलिस आयुक्त को औपचारिक पत्र भेजकर मामले की विस्तृत जांच कराने की मांग की थी। पत्र के माध्यम से धमकी देने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर एवं प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। महापौर कार्यालय ने कहा कि सार्वजनिक संस्थानों और संवैधानिक पदों से जुड़े कार्यालयों को बार-बार इस तरह की धमकियां मिलना गंभीर चिंता का विषय है। ऐसी घटनाओं से न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, बल्कि कर्मचारियों और आम लोगों में भी भय का वातावरण बन सकता है।

खतरनाक और अनधिकृत भवनों पर एमसीडी का शिकंजा

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली में असुरक्षित भवनों, अवैध निर्माण और भवनों के दुरुपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही और एमसीडी आयुक्त संजीव खिरवार ने सभी जोनल उपायुक्तों को अपने-अपने क्षेत्रों में खतरनाक एवं जर्जर भवनों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

एमसीडी अब ऐसे भवनों और संरचनाओं का व्यापक सर्वेक्षण कराएगा, जो मानव जीवन और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। चिन्हित भवनों को उनकी स्थिति और जोखिम के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। इनमें ऐसे भवन भी शामिल होंगे, जो तत्काल रूप से जान-माल के लिए खतरा बने हुए हैं, जबकि कुछ भवनों को छोटी-बड़ी मरम्मत अथवा संरचनात्मक हस्तक्षेप की आवश्यकता के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। महापौर प्रवेश वाही ने अधिकारियों को अनधिकृत निर्माण के मामलों की पहचान कर लागू भवन उपविधियों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पेइंग गेस्ट (पीजी) आवासों, स्कूलों, होटलों और स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यापक निरीक्षण करने को कहा गया है। निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित भवनों के पास सभी अनिवार्य स्वीकृतियां, अनुमतियां और जरूरी दस्तावेज मौजूद हों तथा वे वैध हों। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित भवनों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त संजीव खिरवार ने जोनल उपायुक्तों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन भवनों से तत्काल खतरा उत्पन्न हो रहा है, उनके मामले में कार्रवाई में किसी प्रकार की देरी न हो। आवश्यकता पड़ने पर लागू कानून के तहत सीलिंग और ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ऐसे अनधिकृत और अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई की जाएगी, जिनसे भवन की संरचनात्मक सुरक्षा प्रभावित हो रही है अथवा वहां रहने वाले लोगों और आम जनता के जीवन पर खतरा पैदा हो रहा है। एमसीडी आयुक्त संजीव खिरवार ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। निगम का रवैया केवल हादसे के बाद कार्रवाई करने वाला नहीं, बल्कि सक्रिय और निवारक होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक खतरनाक भवन, अनधिकृत निर्माण और ऐसे संरचनात्मक उल्लंघन की पहचान की जाए, जिससे लोगों के जीवन को खतरा हो सकता है। ऐसे मामलों में कानून के अनुसार त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आयुक्त ने विशेष रूप से बच्चों और विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। अधिकारियों से भवनों की स्थिति की नियमित निगरानी करने और भवन मानदंडों व सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। एमसीडी ने सभी संबंधित विभागों और क्षेत्रीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। निगम का कहना है कि जहां भी भवन नियमों का उल्लंघन अथवा असुरक्षित परिस्थितियां सामने आएंगी, वहां तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की इस कवायद को राजधानी में जर्जर और अनधिकृत भवनों से जुड़े संभावित हादसों को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बीयर की बोतल के पैसे मांगने पर दुकानदार पर चाकू से हमला, गोली चलाई

नई दिल्ली। राज पार्क इलाके में एक चाय दुकानदार पर चाकू और गोली चलाने के आरोप में चार बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना चार सितंबर की आधी रात को हुई जब दुकानदार ने बीयर के पैसे मांगे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो पिस्टल, चार कारतूस, दो चाकू, दो चोरी की बाइक और वारदात में इस्तेमाल दो स्कूटी बरामद की हैं।

बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि पवन नामक युवक अपनी चाय की दुकान बंद कर रहा था। इसी दौरान रवि उर्फ किट्टू अपने साथियों शिवम, अभिषेक और मोनू के साथ दो स्कूटी पर वहां पहुंचा। आरोपियों ने दुकान से बीयर की बोतल ली। दुकानदार ने पैसे मांगने पर रवि ने पवन पर गोली चला दी। पवन ने झुककर अपनी जान बचाई। अन्य आरोपियों ने उस पर चाकू से कई वार किए। उसकी पीठ और कमर के निचले हिस्से में चोटें आईं। पीड़ित के बयान पर हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज की। छह सितंबर को पुलिस को मंगोलपुरी में आरोपियों के होने की सूचना मिली। पुलिस ने दबिश देकर शिवम, अभिषेक और मोनू को गिरफ्तार किया। मोनू के पास से एक पिस्टल और दो कारतूस बरामद हुए, जबकि अभिषेक और शिवम के पास से एक-एक चाकू मिला। इनकी निशानदेही पर फरार रवि को बहादुरगढ़ के किसान चौक से गिरफ्तार किया गया। रवि के पास से एक पिस्टल, दो कारतूस और दो चोरी की बाइक भी बरामद हुई हैं। जांच में सामने आया कि मोनू और अभिषेक कालिंदी कुंज इलाके में भी वांछित थे। तीन सितंबर को वहां दर्ज हत्या के प्रयास और गोलीबारी के एक मामले में ये आरोपी थे। उस वारदात में शिकायतकर्ता को गोली लगी थी। पुलिस के अनुसार, मोनू का संबंध लेफ्टी गिरोह से है। वह नेब सराय थाने का घोषित बदमाश भी है।

लागू होगी पीजी नीति, जरूरी होगा लाइसेंस, जोनवार किराया सीमा होगी तय

नई दिल्ली। सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने पीजी नीति लागू करने का फैसला किया है। जल्द इसका मसौदा तैयार किया जाएगा। नीति के तहत पीजी चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी होगा। मंगलवार को शहरी विकास और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली सचिवालय में पीजी और किराये के मकानों में रहने वाले विश्वविद्यालय के छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान सूद ने कहा कि एक से दो महीने के भीतर इस नीति को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। सूद ने प्रस्तावित पेइंग गेस्ट आवास विनियमन एवं सुरक्षा विधेयक 2026 के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति में पीजी संचालन के लिए अनिवार्य लाइसेंस, जोनवार किराया सीमा समेत अग्नि सुरक्षा ऑडिट तथा एक केंद्रीय पीजी पोर्टल की व्यवस्था होगी। पोर्टल पर छात्रों को पीजी का किराया, सुविधाएं और सुरक्षा ऑडिट की स्थिति जैसी जानकारी पहले से उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार पहले से पीजी नीति और न्यायमूर्ति गौबा समिति की रिपोर्ट को लागू करने पर काम कर रही थी।इसके अलावा विश्वविद्यालयों और नरेला समेत खाली पड़ी सरकारी इमारतों में छात्रावास बनाने की संभावनाएं भी तलाशी जा रहीं हैं। बता दें कि इस विषय पर दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की संयुक्त अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में चर्चा भी हो चुकी है।

सत्य निकेतन हादसे के बाद छात्रों में डर, मुफ्त सरकारी आवास की मांग तेज

सद्भावना टुडे, मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने की घटना के बाद निजी पीजी में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता के बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से बाहर से पढ़ने आने वाले छात्रों के लिए तत्काल बिना किसी शुल्क के वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने की मांग की है। देवेंद्र यादव ने कहा कि सत्य निकेतन हादसे के बाद छात्र निजी मकानों में संचालित पीजी में रहने से डर रहे हैं। ऐसे में सरकार को पीजी के स्ट्रक्चरल ऑडिट और कार्रवाई से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन छात्रों के सामने रहने का संकट पैदा होगा, उनके लिए सुरक्षित और स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध हो।

उन्होंने सवाल उठाया कि डीडीए और एमसीडी की खाली इमारतों को छात्रों के वैकल्पिक आवास के रूप में इस्तेमाल करने की संभावनाओं की जांच के आदेश से क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के करीब 2.5 लाख छात्रों, जिनमें आधे से अधिक छात्र देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली पढ़ने आते हैं, के लिए पर्याप्त आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 91 कॉलेजों में से 71 कॉलेजों में हॉस्टल की व्यवस्था है, लेकिन इनमें कुल मिलाकर अधिकतम करीब 9 हजार सीटें ही उपलब्ध हैं। वहीं, दिल्ली में सरकारी हॉस्टलों की कुल क्षमता लगभग 30 हजार सीटों की है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष करीब 71 हजार छात्र हॉस्टल की मांग करते हैं, लेकिन इनमें से केवल लगभग 10 प्रतिशत छात्रों को ही हॉस्टल की सुविधा मिल पाती है। यह स्थिति राजधानी में बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के सामने मौजूद आवास संकट की गंभीरता को दर्शाती है। यादव ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह भी यह कह चुके हैं कि अगले वर्ष तक हॉस्टल की सीटें दोगुनी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आवश्यकता पूरी नहीं होगी। ऐसे में दिल्ली सरकार, डीडीए और दिल्ली विश्वविद्यालय को मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान तलाशना होगा।

देवेंद्र यादव ने कहा कि पर्याप्त संख्या में सरकारी और विश्वविद्यालय हॉस्टल उपलब्ध नहीं होने के कारण हजारों छात्र निजी मकानों में संचालित पीजी में रहने को मजबूर हैं। इसलिए इन पीजी में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एक तरफ उपराज्यपाल ने डीडीए और भूमि एवं विकास विभाग को विश्वविद्यालयों में नए हॉस्टल के लिए एनओसी, आवश्यक मंजूरियां और निर्माण के लिए एफएआर से संबंधित सहयोग देने के निर्देश दिए हैं। वहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि कई हॉस्टलों पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन मंजूरियों और फंड जुटाने जैसी प्रक्रियाओं में काफी समय लग रहा है। यादव ने कहा कि हॉस्टल निर्माण के लिए निजी भागीदारों के साथ संभावनाएं तलाशने पर भी जोर दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के मौजूदा भ्रष्टाचारपूर्ण शासन में यह व्यवस्था कितनी प्रभावी ढंग से लागू हो पाएगी।

कांग्रेस नेता ने आशंका जताई कि निजी मकानों में चल रहे पीजी के स्ट्रक्चरल ऑडिट के नाम पर निगम अधिकारी कहीं इसे उगाही का साधन न बना लें। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों के सामने यह भी एक बड़ी चिंता है कि ऑडिट और कार्रवाई की प्रक्रिया पारदर्शी हो तथा किसी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हादसे को लेकर सरकार को फटकार लगाते हुए अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पहले ही यह सवाल उठा चुकी है कि हादसे वाली इमारत के निर्माण के लिए वैध मंजूरी ली गई थी या नहीं और यदि मंजूरी दी गई थी तो वह किस अधिकारी ने दी थी। देवेंद्र यादव ने कहा कि उपराज्यपाल के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री, एनडीआरएफ प्रमुख, निगम आयुक्त, पुलिस आयुक्त, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति और डीडीए के अधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस की चिंता यह है कि पीजी के स्ट्रक्चरल ऑडिट और उसकी समीक्षा के नाम पर भाजपा सरकार कहीं लोगों और छात्रों को परेशान न करे। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने भी माना है कि छात्रों की समस्या गंभीर है और इसका समाधान जरूरी है। इसलिए बिना सोचे-समझे सीलिंग की कार्रवाई से बचना होगा। यदि बड़ी संख्या में पीजी सील किए गए और छात्रों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था नहीं की गई तो लाखों छात्र बेघर होने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। देवेंद्र यादव ने दोहराया कि दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को तत्काल हस्तक्षेप करते हुए बाहर से दिल्ली आने वाले छात्रों के लिए सुरक्षित, निःशुल्क और अस्थायी आवास की व्यवस्था करनी चाहिए तथा साथ ही सरकारी और विश्वविद्यालय हॉस्टलों की क्षमता बढ़ाने के लिए समयबद्ध स्थायी योजना तैयार करनी चाहिए।

सर्दियों में धूल रोकने के लिए सड़कों पर उतरेंगी 200 एंटी-स्मॉग गन

नई दिल्ली। सर्दियों में दिल्ली की सड़कों पर उठने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) करीब 200 ट्रक-माउंटेड एंटी-स्मॉग गन सड़कों पर उतारने की तैयारी कर रहा है। इन गाड़ियों के जरिए प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के साथ सड़क और पेड़ों की धुलाई भी की जाएगी। अलग-अलग सड़क मंडलों में जरूरत के हिसाब से इनकी तैनाती की जाएगी। योजना के तहत सेंट्रल और नई दिल्ली रोड डिवीजन में 10, एसआरडी में आठ, नॉर्थ-वेस्ट रोड डिवीजन-2 में 10 और नॉर्थ-वेस्ट रोड डिवीजन-1 में 19 गाड़ियां चलाने की तैयारी है। इनके अलावा दूसरे सड़क मंडलों में भी कम संख्या में एंटी-स्मॉग गन तैनात की जाएंगी। इस तरह पूरी व्यवस्था में करीब 200 गाड़ियां शामिल होंगी। पीडब्ल्यूडी के अनुसार, इन गाड़ियों में कम से कम 8,000 लीटर क्षमता का पानी का टैंकर होगा। एंटी-स्मॉग गन को ट्रक पर लगाया जाएगा और इससे कम से कम 30 मीटर की दूरी तक पानी की महीन फुहार छोड़ी जा सकेगी। गाड़ियों में आगे और पीछे कैमरे तथा जीपीएस की सुविधा भी होगी। एक गाड़ी में चालक के अलावा एक ऑपरेटर और एक सहायक की व्यवस्था रहेगी।

एक नजर

बंगला साहिब में कड़ाह प्रसाद की पर्ची के लिए सेल्फ-सर्विस मशीन लगाई

नई दिल्ली। गुरुद्वारा बंगला साहिब में आने वाली संगत की सुविधा के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कड़ाह प्रसाद की पर्ची लेने के लिए ऑटोमेटिक सेल्फ-सर्विस मशीन शुरू की है। इससे श्रद्धालुओं को पर्ची लेने के लिए लंबी कतार में लगने से राहत मिलेगी। कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और महासचिव सरदार जगदीप सिंह काहलों ने बताया कि ऐतिहासिक गुरुद्वारा बंगला साहिब में मशीन की शुरुआत हेड ग्रंथी ज्ञानी रणजीत सिंह की ओर से अरदास के बाद की गई। इसमें उपलब्ध क्यूआर कोड के माध्यम से संगत आसानी से कड़ाह प्रसाद की पर्ची प्राप्त कर सकेगी। उन्होंने कहा कि गुरुपर्व और छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारा साहिब में पहुंचते हैं। ऐसे में कड़ाह प्रसाद की पर्ची के लिए लगने वाली कतार को कम करने में यह मशीन उपयोगी साबित होगी। कमेटी पदाधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में दिल्ली के अन्य गुरुद्वारा साहिबों में भी ऐसी सेल्फ-सर्विस मशीनें स्थापित करने की योजना है।

प्रदूषण रोकने के लिए ट्रायर धुलाई के बाद लैंडफिल से बाहर निकलेंगे वाहन

नई दिल्ली। राजधानी में वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने बड़ा कदम उठाया है। अब गाजीपुर, ओखला और भलस्वा लैंडफिल साइट से कूड़ा डालकर बाहर निकलने वाली गाड़ियां पूरी तरह धुलने के बाद ही सड़क पर आ सकेंगी। इसके लिए तीनों साइटों पर स्वचालित व्हील वॉश सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके लिए निगम ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। लैंडफिल साइट पर कूड़ा डालने के दौरान वाहनों के टायरों में भारी गंदगी और कीचड़ जम जाता है। बिना धुले जब ये गाड़ियां बाहर निकलती हैं तो जिन रास्तों से गुजरती हैं, वहां टायरों से गंदगी फैलती रहती है। यह गंदगी सूखने के बाद हवा के साथ उड़कर धूल कणों के रूप में वायु प्रदूषण बढ़ाती है, जिससे आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। दिल्ली नगर निगम के मुताबिक, दिल्ली के इन तीनों प्रमुख लैंडफिल साइटों पर रोजाना तीन हजार मीट्रिक टन से अधिक कूड़ा पहुंचाया जाता है, जबकि पूरी दिल्ली से प्रतिदिन लगभग 11 हजार मीट्रिक टन से अधिक ठोस कचरा निकलता है। नई व्यवस्था के तहत हर वाहन को सेंसर आधारित वॉश बे से गुजरना अनिवार्य होगा। टायर सफाई के बाद ही ट्रैफिक सिग्नल हरा होगा और वाहन बाहर निकल सकेगा।

शिक्षकों को उत्तराखंडी लोकभाषा और संस्कृति सहेजने पर मिला सम्मान

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में उत्तराखंड की संस्कृति और लोकभाषाओं को जीवित रखने में पूर्वी दिल्ली के शिक्षकों का अहम योगदान सामने आया है। दिल्ली गढ़वाली-कुमाऊनी-जौनसारी अकादमी की ओर से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में पूर्वी दिल्ली के विभिन्न केंद्रों से जुड़े शिक्षकों को उनकी समर्पित सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। वर्ष 2012 से यह मंच गर्मियों की छुट्टियों में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं की विशेष कक्षाएं और कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है। इस वर्ष जून से अगस्त तक चले इस अभियान के तहत पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में कक्षाएं लगाई गईं। यहां के शिक्षकों और केंद्र संयोजकों ने बच्चों को मातृभाषा के साथ-साथ उत्तराखंड की समृद्ध परंपराओं से जोड़ा। समारोह में प्रत्येक केंद्र से चार-चार शिक्षकों और दो केंद्र संयोजकों को मंच पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण भगवत मनराल की टीम द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाल गीत और उत्तराखंड से हो रहे पलायन पर आधारित नाटक रहा। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिक्षकों के जज्बे की सराहना की। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और मातृभाषा से जोड़ना बेहद जरूरी है। मंच के संरक्षक डॉ. विनोद बछेती और शौर्य डोभाल ने भी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने पर बल दिया। इस अवसर पर निगम पार्षद बीएस पवार, नीता बिष्ट, यशपाल कैंतुरा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

गोल्फ कोर्स परियोजना को आगे बढ़ाने के निर्देश

नोएडा। प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक कुमार ने सेक्टर-151ए में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के निर्माण कार्य की समीक्षा की। करीब डेढ़ वर्ष से बंद काम को लेकर जानकारी ली। उन्होंने इस परियोजना की अड़चनों को दूर परियोजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। चेयरमैन की समीक्षा बैठक में सीईओ, एसीईओ और गोल्फ कोर्स परियोजना से संबंधित विभाग के अधिकारी थे। प्राधिकरण के अधिकारियों ने चेयरमैन को बताया कि पुरानी एजेंसी काम में लगातार लापरवाही बरत रही थी। नोटिस के बाद भी काम में तेजी नहीं ला रही थी। इसकी वजह से पिछले साल जुलाई में एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसके अलावा उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। अब नई एजेंसी के चयन की प्रक्रिया चल रही है। एक बार जारी किए गए टेंडर में किसी एजेंसी का चयन नहीं हो सका था। अब दोबारा टेंडर जारी किया हुआ है।

दिल्ली : घर के बाहर शराब पीने और शोर करने से रोका तो मणिपुरी संगीतकार पर किया हमला, मौत

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली के किलोकरी गांव में 54 वर्षीय मणिपुरी संगीतकार सी. विक्रम सिंह की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, उनके घर के बाहर शराब पीने और शोर मचाने को लेकर कुछ डिलीवरी कर्मियों और ढाबा कर्मचारियों के साथ उनका विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद आरोपियों ने विक्रम सिंह पर लात-घूंसों से हमला कर दिया।

पुलिस के मुताबिक, सनलाइट कॉलोनी थाने को विक्रम सिंह पर हमले की सूचना पीसीआर कॉल के जरिए मिली थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि मणिपुर के रहने वाले विक्रम सिंह कई सालों से किलोकरी गांव में रह रहे थे। घटना के समय उनके अपार्टमेंट के बाहर कुछ लोग कथित तौर पर शराब पी रहे थे और तेज आवाज में शोर कर रहे थे। विक्रम ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। पुलिस के अनुसार, कहासुनी जल्द ही मारपीट में बदल गई। आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने विक्रम सिंह पर लगातार मुक्कों और घूंसों से हमला किया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद उनका बेटा याइफाबा उन्हें तुरंत होली फैमिली अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया। पुलिस ने इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 19 वर्षीय भरत कुमार, 26 वर्षीय प्रमोद, 22 वर्षीय रमजान खान, 21 वर्षीय दीपांशु, 32 वर्षीय मोहन विश्वकर्मा, 36 वर्षीय विजय और 26 वर्षीय मन्नू के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि ये सभी अलग-अलग ढाबों और फूड स्टॉल पर काम करते हैं। घटना के बाद नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स सोसाइटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी (एनईएसएसडीयू) ने भी विक्रम सिंह की मौत पर दुख जताया। संगठन ने उन्हें एक सम्मानित मणिपुरी संगीतकार बताते हुए घटना की निंदा की। ऑर्गनाइजेशन ने कहा कि विक्रम ने अपने अपार्टमेंट के बाहर कुछ लोगों को कथित तौर पर शराब पीते और शोर करते देखा था। इसके बाद वह नीचे गए और उनसे आवाज कम करने के लिए कहा, जिसके बाद उन पर हमला किया गया और उन्हें गंभीर चोटें आईं। छात्र संगठन ने इस घटना को 'बेवजह की हिंसा' करार देते हुए प्रशासन से मामले की तेज, निष्पक्ष और पूरी जांच की मांग की है। संगठन ने कहा है कि जांच में जो लोग दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस घटना के पीछे के पूरे विवाद और हमले की परिस्थितियों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और जांच के आधार पर अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डीटीसी ड्राइवर को 34 साल बाद दोषमुक्ति, हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी रद्द की

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के एक ड्राइवर को 34 साल बाद आरोपों से मुक्त कर दिया है। अदालत ने ड्राइवर की बर्खास्तगी को खारिज करते हुए औद्योगिक ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच प्रक्रिया में ड्राइवर को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया था।

न्यायमूर्ति अमित महाजन ने अपने फैसले में औद्योगिक ट्रिब्यूनल के निर्णय को तर्कसंगत बताया। अदालत ने कहा कि इसमें कोई विसंगति या त्रुटि नहीं है। डीटीसी में ड्राइवर श्याम सुंदर ने 7 मई 1992 को बिना अनुमति के ड्यूटी छोड़ दी थी। इसके बाद 18 जून 1992 को उन्हें अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए आरोप पत्र जारी किया गया। ड्राइवर ने जवाब में बताया कि उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। उन्होंने एक सहकर्मी के माध्यम से छुट्टी के आवेदन भी भेजे थे। जांच अधिकारी ने ड्राइवर के जवाब को आरोप स्वीकार करने के आधार पर खारिज कर दिया। बिना किसी और सबूत या गवाही के जांच समाप्त कर दी गई। 17 मई 1993 को ड्राइवर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि ड्राइवर ने अनुपस्थिति स्वीकार की थी। लेकिन उसने पत्नी की बीमारी का वाजिब कारण भी बताया था। अदालत ने कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जांच अधिकारी ने ड्राइवर के जवाब के बावजूद आरोप स्वीकार मान लिए थे। यह बिना किसी और सबूत के किया गया था। 27 अप्रैल 2001 के ट्रिब्यूनल के आदेश को डीटीसी ने कभी चुनौती नहीं दी।

यूजीसी नेट री-एग्जाम : दिल्ली के उम्मीदवारों को सलाह, 9-10 सितंबर को ट्रैफिक पाबंदियों को देखकर निकलें

नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने दिल्ली में यूजीसी नेट जून 2026 की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से ही बना लें क्योंकि 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में यात्रा प्रतिबंधों की संभावना है, जिससे सड़क यात्रा लंबी हो सकती है और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में देरी हो सकती है। परीक्षार्थियों के लिए जारी एक सलाह में परीक्षा देने वाली एजेंसी ने परीक्षा में शामिल होने वाले सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने यात्रा मार्गों की पहले से जांच कर लें, समय से पहले निकलें और निर्धारित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के दौरान संभावित यातायात प्रतिबंधों, मार्गों में बदलाव या देरी को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त अतिरिक्त समय अपने पास रखें।

यह ऐसे समय में हो रहा है जब भारत 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। एनटीए ने कहा कि उम्मीदवारों को पहले से ही उचित व्यवस्था करनी चाहिए और यात्रा के समय में वृद्धि की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वे रिपोर्टिंग समय से काफी पहले अपने संबंधित परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सकें और अंतिम समय की किसी भी कठिनाई से बच सकें। अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की पुनर्परीक्षा देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के अनुसार, पुनर्परीक्षा 9 और 10 सितंबर को होगी। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षाएं 9 सितंबर को आयोजित की जाएंगी। अंग्रेजी की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली शिफ्ट में होगी, जबकि वाणिज्य की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी शिफ्ट में होगी। समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इन तीन विषयों में से किसी एक का चयन किया था, वे आने वाले दिनों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होने वाली पुनर्परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों में कई त्रुटियों के संबंध में राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान (एनटीए) को अनेक शिकायतें प्राप्त होने के बाद पुनर्परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश स्तर के सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति, पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) प्रदान करने के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु यूजीसी-एनईटी परीक्षा आयोजित की जाती है।

रिहायशी इलाके में इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में आग लगी

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

नोएडा। सेक्टर-51 स्थित होशियारपुर गांव की गली नंबर-दो में मंगलवार सुबह इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में आग लग गई। आसपास के घरों और इमारतों में आग फैलने का खतरा पैदा हो गया। अग्निशमन विभाग ने 16 दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। गोदाम मनीष शर्मा का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार मंगलवार सुबह सात बजकर 25 मिनट पर गोदाम से धुआं निकलता दिखाई दिया। शुरुआत में आसपास के लोगों को आग लगने की जानकारी नहीं हुई, क्योंकि गोदाम बाहर से बंद था। करीब 10 मिनट बाद स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग की विकरालता को देखते हुए तत्काल अलग-अलग फायर स्टेशनों से अतिरिक्त दमकल वाहनों को बुलाया गया। जिस समय आग लगी, गोदाम में कोई कर्मचारी या व्यक्ति नहीं था। इसी वजह से शुरुआत में अंदर लगी आग का पता चलने में कुछ समय लगा। आग ने गोदाम में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते अंदर से तेज लपटें निकलने लगीं और काफी दूर तक धुआं दिखाई देने लगा। दमकल की टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती गोदाम के आसपास बने मकान और अन्य इमारतें

थी। गोदाम घनी आबादी वाले रिहायशी क्षेत्र में था, इसलिए आग के आसपास फैलने की आशंका बनी हुई थी। दमकलकर्मियों ने सबसे पहले आसपास के घरों में मौजूद लोगों को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद आग को नियंत्रित करने की कार्रवाई शुरू की गई।

गोदाम बाहर से बंद होने के कारण दमकलकर्मियों को आग बुझाने के लिए अंदर पहुंचने में परेशानी हुई। आग की स्थिति को देखते हुए अग्निशमन विभाग की एक टीम ने ऊपर से गोदाम के टीन शेड को काटा। इसके बाद कर्मचारी अंदर दाखिल हुए और अलग-अलग दिशाओं से पानी की बौछार शुरू की गई। आग को चारों तरफ से बुझाने की कोशिश की गई। दमकलकर्मियों ने गोदाम के साथ-साथ आसपास की इमारतों पर भी लगातार पानी की बौछार की, ताकि आग की गर्मी और लपटें किसी दूसरे भवन तक न पहुंचे। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। गोदाम से निकल रहे धुएं और आग की तेज लपटों के कारण आसपास के लोगों में दहशत का माहौल रहा। स्थानीय लोगों के मुताबिक धुआं काफी दूर से दिखाई दे रहा था। करीब तीन घंटे तक इलाके में अफरातफरी जैसी स्थिति बनी रही। हालांकि, दमकल और पुलिस की टीम की सक्रियता के कारण आग को आसपास के मकानों तक पहुंचने से रोक लिया गया। लोगों का कहना था कि यदि आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो रिहायशी इलाके में बड़ा हादसा हो सकता था।

द्वारका पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महिला उत्पीड़न मामले में फरार घोषित अपराधी गिरफ्तार

नई दिल्ली,एजेंसी। द्वारका जिला पुलिस की एंटी-जेल बेल और भगोड़ा अपराधी सेल ने महिला के खिलाफ क्रूरता के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे घोषित अपराधी (पीओ) को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई जो हरियाणा के झज्जर जिले के कालियावास गांव का निवासी है। उसे 10 जुलाई को डबरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के संबंध में भगोड़ा घोषित किया गया था।

उसे घोषित अपराधी घोषित करने का आदेश दिल्ली के द्वारका कोर्ट, दक्षिण-पश्चिम जिले की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (महिला न्यायालय) सुभी गुप्ता द्वारा पारित किया गया था। पुलिस के अनुसार, द्वारका के पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह के निर्देश पर घोषित अपराधियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर हरीश कुमार कर रहे थे और इसमें हेड कांस्टेबल राहुल यादव और कुलवंत शामिल थे। यह अभियान एसीपी (ऑपरेशन) सुभाष मलिक की देखरेख में चलाया गया। पुलिस ने बताया कि 23 अगस्त को टीम को विशिष्ट सूचना मिली थी कि अनिल कुमार, जो मुकदमे से बच रहा था, झज्जर के बिरोहर गांव और उसके आसपास मौजूद था।

सूचना मिलने पर टीम गांव पहुंची और जाल बिछाया। पुलिस ने बताया कि इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि कुमार के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है।इसी बीच, 29 अगस्त को दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस ने एक अनसुलझे हत्या मामले को सुलझाने का दावा किया था, जिसमें एक 64 वर्षीय व्यक्ति और उसके सहयोगी को एक 38 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जो आरोपियों में से एक का बेटा था। आरोपियों की पहचान 64 वर्षीय तालुकदार अंसारी और 49 वर्षीय मोहम्मद वसीम उर्फ अकरम के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित गुल हसन को डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने एक सुनसान कंटेनर में ले जाया गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई।

बिहारीपुर नाले के 650 मीटर हिस्से को ढकेगा विभाग

नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाकों में जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने बिहारीपुर नाले के 650 मीटर लंबे हिस्से को सुरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत नाले के ऊपर स्ट्रक्चरल स्टील फ्रेम व लोहे की जाली (प्रोटेक्शन मेश) लगाई जाएगी, ताकि नाले में निर्माण सामग्री व ठोस कचरा गिरने से रोका जा सके।

दिल्ली सरकार व नगर निगम हर साल नालों की सफाई व गाद निकासी पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। विभाग का मानना है कि जाली लगने से दोबारा कचरा नहीं गिरेगा, जिससे बार-बार होने वाले सफाई खर्च में कमी आएगी और जल निकासी लंबे समय तक प्रभावी बनी रहेगी। यह नाला बिहारीपुर गांव, बिहारीपुर एक्सटेंशन, खजूरी खास, सभापुर व करावल नगर की जल निकासी से जुड़ा है।

गुरुग्राम में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ गरजे सफाईकर्मी

गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को पुराने नगर निगम कार्यालय में इकट्ठा होकर धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कुरुक्षेत्र नगर परिषद के पैरोल कर्मचारी रोहित पुत्र रामकुमार और करनाल नगर निगम के कुलदीप पुत्र राजवीर की टर्मिनेशन के सदमे से हार्ट अटैक से मौत पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। 34वें दिन की हड़ताल की अध्यक्षता वरिष्ठ उप प्रधान सम्मी बोहत और फायर जिला प्रधान साहुन खान ने संयुक्त रूप से की। संचालन सचिव धर्मेंद्र जिंघाला और कोषाध्यक्ष भारत कांगड़ा ने किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि नौ सितंबर तक समाधान नहीं हुआ तो हड़ताल आगे बढ़ाई जाएगी। पुराना नगर निगम कार्यालय परिसर में मृतक सफाई कर्मचारियों को श्रद्धांजलि के बाद सभी हड़ताली कर्मचारियों ने उल्टी झाड़ू करके और काले झंडे लेकर अग्रसेन चौक, शमा रेस्टोरेंट, सेशन हाउस, पटवार भवन, झाड़सा रोड, सिविल लाइन रोड, मोरनी चौक, धर्मशाला चौक होते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राज्य उप प्रधान बसंत कुमार ने कहा कि मृतक दोनों कर्मचारियों के परिवार को उचित मुआवजा और आश्रित को पक्की नौकरी दी जाए। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की गिरफ्तारी, सस्पेंशन और टर्मिनेशन रद्द करने और झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग की। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने अभी तक कोई मांग नहीं मानी और न कोई पत्र जारी किया, जबकि मंत्री सोशल मीडिया पर 12-14 मांगें मानने का दावा कर रहे हैं। यह झूठी बयानबाजी है। उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलन को बातचीत से हल करने के बजाय पुलिस बल से दबा रही है। शहर में कूड़ा उठाने के सरकारी प्रयास विफल हैं। फर्जी बिल बनाकर सरकारी धन की लूट हो रही है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नेताओं ने मांग की कि 13 मई के समझौते को लागू कर लिखित आदेश जारी हों, सफाई और सीवर कार्य से ठेका प्रथा खत्म कर पक्की भर्ती हो, कच्चे कर्मचारियों का नियमितीकरण हो और फायर कर्मचारी रणबीर व भवी चंद शर्मा के आश्रितों को वादे के अनुसार 50-50 लाख सहायता और पक्की नौकरी दी जाए।

दिल्ली विस, सरदार पटेल विद्यालय और कई सरकारी दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा, सरदार पटेल विद्यालय और कई सरकारी संस्थानों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) लागू किया और प्रभावित जगहों पर बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी। मंगलवार सुबह के समय धमकी मिलने के बाद, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली पुलिस, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड, डॉग यूनिट और दिल्ली फायर सर्विस की टीमें उन जगहों पर पहुंचीं और संबंधित इलाकों की घेराबंदी कर दी।

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा टीमों द्वारा तलाशी ली गई किसी भी जगह पर अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। परिसरों की अच्छी तरह से जांच की जा रही है और अधिकारी एहतियाती इंतजामों के तहत स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ईमेल और धमकी के स्रोत की आगे की जांच चल रही है। यह ताजा धमकी दिल्ली विधानसभा को लेकर पहले से मौजूद सुरक्षा चिंताओं के बीच आई है, जिसे पहले भी इसी तरह की बम की धमकियां मिल चुकी हैं। इससे पहले, 14 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट समेत दिल्ली की कई जगहों पर बम की धमकियां मिली थीं, जिसके कारण स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए थे।

दिल्ली हाईकोर्ट को यह धमकी ईमेल के जरिए मिली थी, जिसमें 15 अगस्त को दोपहर 2:11 बजे कोर्ट में कथित धमाके की चेतावनी दी गई थी। उसी ईमेल में 15 अगस्त को दोपहर 3:11 बजे दिल्ली की जिला अदालतों में भी धमाकों की धमकी दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के अलावा, पांच अन्य जगहों पर फोन कॉल के जरिए बम की धमकियां मिली थीं। इनमें जामनगर हाउस, झंडेवालान बिल्डिंग, एमबी रोड साकेत ऑफिस, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 और दिल्ली कैंटोनमेंट में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ऑफिस शामिल थे। दिल्ली के अलावा इससे पहले महाराष्ट्र के नागपुर में भी धमकी भरा मेल मिल चुका है। 18 अगस्त को नागपुर में एक दर्जन से ज्यादा स्कूलों को बम विस्फोट की धमकी मिली थी। हालांकि, जब तलाशी ली गई तो स्कूलों से कोई संदिग्ध या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ।

त्योहारी सीजन में चलेंगी चार स्पेशल ट्रेनें

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। इस सीजन में चार आरक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें आनंद विहार टर्मिनल से लौकहा बाजार (बिहार) और पाटलिपुत्र के लिए दैनिक ट्रेनों के संचालन के साथ योगनगरी ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर के बीच साप्ताहिक और हजरत निजामुद्दीन-दादर के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन सेवा शुरू होगी। इससे दिल्ली से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मुंबई जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।

रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 04014/04013 आनंद विहार टर्मिनल-लौकहा बाजार-आनंद विहार टर्मिनल आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल 16 सितंबर से 29 नवंबर तक आनंद विहार से और 17 सितंबर से 30 नवंबर तक लौकहा बाजार से रोजाना चलेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 04314/04313 योगनगरी ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर-योगनगरी ऋषिकेश आरक्षित साप्ताहिक स्पेशल चार अक्तूबर से 29 नवंबर तक ऋषिकेश से और 5 अक्तूबर से 30 नवंबर तक मुजफ्फरपुर सेचलेगी। यह ट्रेन हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सिवान, छपरा, सोनपुर और हाजीपुर

होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। आनंद विहार से ट्रेन शाम 3:40 बजे रवाना होगी। रास्ते में गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, कप्तानगंज, सिसवा बाजार, बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, सकरी, झंझारपुर और अन्य स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन रात 8:15 बजे लौकहा बाजार पहुंचेगी।

निजामुद्दीन-दादर के बीच सुपरफास्ट ट्रेन

ट्रेन संख्या 04002/04001 हजरत निजामुद्दीन-दादर-हजरत निजामुद्दीन आरक्षित सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल 13 अक्तूबर से 24 नवंबर तक निजामुद्दीन से और 15 अक्तूबर से 26 नवंबर तक दादर से चलेगी। यह ट्रेन मंगलवार को निजामुद्दीन से और बृहस्पतिवार को दादर से चलेगी। इसमें केवल एसी श्रेणी के कोच होंगे। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 04096/04095 आनंद विहार टर्मिनल-पाटलिपुत्र-आनंद विहार टर्मिनल आरक्षित स्पेशल ट्रेन 1 अक्तूबर से 29 नवंबर तक आनंद विहार से और 2 अक्तूबर से 30 नवंबर तक पाटलिपुत्र से चलेगी।

आतंकवाद बोया पाकिस्तान ने, अब सिंधु का पानी भी भूलना होगा

कांतिलाल मांडोत

पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता आया है। सीमा पार से आतंकियों को प्रशिक्षण देना, उन्हें भारत में हिंसा फैलाने के लिए भेजना और आतंकी घटनाओं के बाद भी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करना उसकी नीति का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हर कार्रवाई की एक कीमत होती है और अब पाकिस्तान को अपने इसी रवैये की कीमत पानी के मोर्चे पर चुकानी पड़ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का जो कठोर निर्णय लिया, उसके प्रभाव अब जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। लद्दाख में सिंधु नदी पर चेक डैम का निर्माण इसी बदलती तस्वीर का संकेत है।

लद्दाख के उपशी में सिंधु नदी पर तैयार किया गया पहला रॉक चेक डैम केवल पानी रोकने वाली एक छोटी परियोजना नहीं है। यह बदलते भारत की सोच और उसकी जल नीति का प्रतीक है। जिस सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत ने दशकों तक संधि की मर्यादाओं का पालन किया, उसी नदी के पानी का अपने लोगों के हित में बेहतर इस्तेमाल करने की दिशा में अब कदम बढ़ रहे हैं। उपशी में तैयार चेक डैम में पानी जमा होना और उसके माध्यम से आसपास के खेतों तक सिंचाई पहुंचने की संभावना लद्दाख जैसे दुर्गम और पानी की कमी वाले क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शुरुआत भर है। लद्दाख में सिंधु नदी पर 36 और चेक डैम बनाने की तैयारी की जा रही है। इनमें लेह में सात हिमालयन रॉक चेक डैम और करगिल में 29 चेक डैम प्रस्तावित बताए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं पर करीब 56 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। यानी भारत अब सिंधु नदी को केवल सीमा पार बह जाने वाली नदी के रूप में देखने के बजाय अपने किसानों, अपने गांवों और अपने सीमावर्ती क्षेत्रों की जल जरूरतों से जोड़कर देख रहा है। लद्दाख की परिस्थितियां किसी से छिपी नहीं हैं। ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में पानी का संकट हमेशा बड़ी चुनौती रहा है। खेती का मौसम सीमित है और बुवाई के समय पानी की उपलब्धता किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में चेक डैम जैसी छोटी लेकिन प्रभावी जल संरचनाएं स्थानीय स्तर पर बड़ा बदलाव ला सकती हैं। प्राकृतिक चट्टानों से तैयार की गई ऐसी संरचनाएं पानी को रोकने, भूजल स्तर सुधारने और खेतों तक पानी पहुंचाने में उपयोगी हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाए जा रहे इन ढांचों से जल संरक्षण और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम करने की कोशिश भी दिखाई देती है। पाकिस्तान के लिए परेशानी यहीं से शुरू होती है। दशकों से पाकिस्तान ने सिंधु नदी प्रणाली पर अपनी कृषि और जल व्यवस्था को खड़ा किया है। उसकी बड़ी आबादी की आजीविका खेती से जुड़ी है और सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियां उसके लिए जीवनरेखा जैसी हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझने और आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई करने के बजाय बार-बार वही रास्ता चुना, जिसने दोनों देशों के बीच अविश्वास को गहरा किया। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि पानी कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे आतंकवाद से अलग करके देखा जा सकता है। जब एक देश लगातार दूसरे देश के नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने वाली गतिविधियों को रोकने में विफल रहता है, तो वह द्विपक्षीय संबंधों की बुनियादी जमीन को स्वयं कमजोर करता है। भारत ने वर्षों तक संधि का सम्मान किया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारत ने अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को निभाया। लेकिन जब आतंकवाद लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बनता रहा और पहलगाम जैसी घटना ने देश को झकझोर दिया, तब भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद और सामान्य संबंध एक साथ नहीं चल सकते।

भारत का सिंधु जल संधि को स्थगित करना इसी व्यापक नीति का हिस्सा है। इसका संदेश साफ है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत के साथ सामान्य संबंध बनाए रखने की उम्मीद एक साथ नहीं की जा सकती। पाकिस्तान यदि भारत के खिलाफ आतंक का रास्ता चुनता है तो उसे उसके राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक परिणामों के लिए भी तैयार रहना होगा। अब लद्दाख में सिंधु नदी पर बन रहे चेक डैम पाकिस्तान के लिए एक और संदेश लेकर आए हैं। भारत केवल बयान नहीं दे रहा, बल्कि अपनी जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जमीन पर योजनाएं तैयार कर रहा है। आने वाले समय में यदि सिंधु नदी के पानी के बेहतर उपयोग की और योजनाएं बनती हैं तो पाकिस्तान के लिए यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि पुराने दौर की परिस्थितियां वापस नहीं आने वालीं। पाकिस्तान की सरकार आज यदि अपने लोगों के सामने पानी की समस्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करती है तो यह आधा सच होगा। असली सवाल यह है

कि पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में पहुंचाया किसने। भारत ने तो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है। पहलगाम का आतंकी हमला किसने किया, आतंकियों को किस तरह का समर्थन मिलता रहा, सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ने कितनी ईमानदार कार्रवाई की और दोनों देशों के संबंधों को किसने लगातार खराब किया, इन सवालों से पाकिस्तान की सरकार और उसकी व्यवस्था बच नहीं सकती। करोड़ों पाकिस्तानी नागरिकों के सामने पानी की चुनौती खड़ी होती है तो इसका दोष केवल भारत पर डाल देना आसान राजनीतिक रास्ता हो सकता है, लेकिन यह जनता को सच्चाई से दूर रखने जैसा होगा।

पाकिस्तान की आवाम को यह सवाल अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि भारत के साथ दुश्मनी और आतंकवाद की नीति ने देश को क्या दिया। आर्थिक संकट से जूझता पाकिस्तान पहले ही अनेक मोर्चों पर परेशान है। ऐसे में पानी जैसी मूलभूत जरूरत से जुड़ा संकट उसके लिए और गंभीर चुनौती बन सकता है। भारत के लिए यह अवसर केवल पाकिस्तान पर दबाव बनाने का नहीं, बल्कि अपने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास का भी है। लद्दाख में जल संरक्षण की योजनाएं वहां के किसानों और स्थानीय आबादी के लिए राहत लेकर आ सकती हैं। सिंधु का पानी यदि स्थानीय जरूरतों के लिए संरक्षित किया जाता है तो इससे खेती, पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। सीमा से लगे क्षेत्रों में विकास अपने आप में राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करता है। यह भी समझना जरूरी है कि पानी का इस्तेमाल केवल राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संसाधन के रूप में होना चाहिए। भारत को अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपने जल संसाधनों का अधिकतम वैध और वैज्ञानिक उपयोग करना चाहिए। सिंधु नदी पर चेक डैम जैसी परियोजनाएं इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम बन सकती हैं। पाकिस्तान को अब यह समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद के सहारे भारत को दबाव में लाने का दौर समाप्त हो चुका है। भारत न तो आतंकवादी हमलों को सामान्य घटना मानने के लिए तैयार है और न ही अपनी सुरक्षा तथा संसाधनों के सवाल पर पुरानी मानसिकता में रहने वाला है। यदि पाकिस्तान को अपने लोगों के लिए पानी चाहिए तो सबसे पहले उसे भारत के खिलाफ आतंकवाद की नीति पर पुनर्विचार करना होगा। सिंधु नदी सदियों से बह रही है और आगे भी बहती रहेगी। लेकिन उसके पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो व्यवस्था बनी थी, वह आपसी विश्वास और शांतिपूर्ण संबंधों की भावना पर टिकी थी। जब विश्वास ही लगातार तोड़ा गया तो उस व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक था। पहलगाम के बाद भारत ने इसी संदेश को स्पष्ट किया है। अब पाकिस्तान के लिए बेहतर यही होगा कि वह सिंधु जल को लेकर भारत को कोसने के बजाय अपने गिरेबान में झांके। जिस आतंकवाद को उसने वर्षों तक भारत के खिलाफ नीति का हिस्सा बनाए रखा, उसी ने आज उसके सामने अनेक संकट खड़े कर दिए हैं। भारत ने अपने पानी को बचाने और उसका अपने लोगों के हित में उपयोग करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। उपशी का चेक डैम इसी बदलते युग की पहली झलक है।

पाकिस्तान की सरकार यदि आज भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करती और अपनी जनता की परेशानियों का पूरा दोष भारत पर डालती रहती है तो वह अपने ही लोगों के साथ छल करेगी। आतंकवाद की आग पाकिस्तान ने स्वयं भड़काई है। अब उस आग की कीमत उसकी जनता को चुकानी पड़ रही है। इसलिए पाकिस्तान के लिए समय रहते यह समझ लेना ही बेहतर होगा कि भारत के साथ शांति, सहयोग और आतंकवाद-मुक्त संबंधों के बिना पुराने दौर की सुविधाओं की उम्मीद करना व्यर्थ है। सिंधु का पानी अब भारत की जल सुरक्षा, सीमावर्ती विकास और किसानों की जरूरतों से भी जुड़ रहा है। पाकिस्तान को इसे एक चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि अपने किए पर विचार करने का अवसर समझना चाहिए। यदि वह आतंकवाद की राह नहीं छोड़ता तो आने वाले समय में उसके लिए सबसे कठिन सवाल यही हो सकता है कि उसने भारत से दुश्मनी के नाम पर आखिर अपने ही लोगों का कितना नुकसान कर दिया। अब पाकिस्तान के लिए सिंधु जल को लेकर पुराने भरोसे में बैठे रहना भूल साबित होगा। उसे यह समझना होगा कि भारत बदल चुका है, उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं और आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति भी पहले जैसी नहीं रही। पाकिस्तान ने जिस रास्ते को चुना था, उसी रास्ते ने उसे इस मोड़ तक पहुंचाया है। अब आगे की दिशा भी उसे ही तय करनी होगी।

सागर की घटना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि शुरुआती सूचनाओं में ही बड़ी संख्या में लोगों के प्रभावित होने की बात सामने आई। अस्पतालों में मरीज पहुंचने लगे, कुछ की हालत गंभीर हुई और प्रशासन को प्रभावित गांवों में चिकित्सा दल भेजकर लोगों की जांच करनी पड़ी। नकली शराब की बोतलों और उनके स्रोत की जांच के साथ यह भी देखा जा रहा है कि अवैध शराब का नेटवर्क कितने गांवों और कितने इलाकों तक फैला हुआ था। यदि जांच में अंतरराज्यीय आपूर्ति की पुष्टि होती है तो यह मामला केवल स्थानीय स्तर पर अवैध शराब बेचने का नहीं, बल्कि एक बड़े नेटवर्क की ओर संकेत करेगा। सागर की घटना कोई अकेला मामला नहीं है। वर्ष 2026 में देश के कई हिस्सों से जहरीली या मिलावटी शराब से मौतों की खबरें सामने आई हैं। बिहार में मार्च और अप्रैल के दौरान ऐसी घटनाओं ने फिर चिंता बढ़ाई। मार्च में सारण जिले में संदिग्ध जहरीली शराब के सेवन के बाद पांच लोगों की मौत की खबर सामने आई और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि प्रशासन ने कुछ मौतों के कारणों पर अलग राय रखी थी, लेकिन परिजनों और स्थानीय लोगों ने शराब सेवन को मौतों से जोड़ा था। इसके बाद अप्रैल में पूर्वी चंपारण में मिलावटी शराब से मौतों का मामला सामने आया। शुरुआती तौर पर चार-पांच मौतों की जानकारी सामने आई, लेकिन बाद में मृतकों की संख्या सात तक पहुंची।

जहरीली शराब का जहरः कुछ घूंट और उजड़ जाता है पूरा परिवार

कांतिलाल मांडोत

शराब की कुछ घूंटें किसी व्यक्ति की जिंदगी ही नहीं, उसके पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ सकती हैं। मध्यप्रदेश के सागर जिले से सामने आई जहरीली शराब की घटना ने एक बार फिर देश को उसी पुराने और भयावह सवाल के सामने खड़ा कर दिया है कि आखिर अवैध शराब का कारोबार बार-बार लोगों की जान लेने के बाद भी क्यों नहीं रुकता। बंडा तहसील के गूगरा खुर्द, नौराज, बराज और आसपास के गांवों में कथित नकली शराब पीने के बाद बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने और मौतों का सिलसिला सामने आया है। छह सितंबर तक उपलब्ध रिपोर्टों में मृतकों की संख्या 11 तक पहुंच चुकी थी और 54 लोगों के प्रभावित होने की सूचना थी। जांच में शराब की आपूर्ति का तार उत्तर प्रदेश के ललितपुर से जुड़ने की आशंका सामने आई है। प्रशासन ने शराब की दुकानों को सील किया है और आबकारी तथा पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। इस घटना की सबसे बड़ी त्रासदी केवल मौतों की संख्या नहीं है। इसके पीछे वे परिवार हैं जिनके घर का कमाने वाला व्यक्ति अचानक दुनिया छोड़ देता है। किसी घर में बच्चों के सिर से पिता का साया उठता है, किसी परिवार में पति की मौत के बाद पत्नी के सामने बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है और कहीं बूढ़े माता-पिता अपने जवान बेटे की अर्थी उठाने को मजबूर हो जाते हैं। जहरीली शराब का कारोबार करने वालों के लिए यह भले ही अवैध कमाई का जरिया हो, लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए यह जीवनभर का दर्द बन जाता है। सागर की घटना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि शुरुआती सूचनाओं में ही बड़ी संख्या में लोगों के प्रभावित होने की बात सामने आई। अस्पतालों में मरीज पहुंचने लगे, कुछ की हालत गंभीर हुई और प्रशासन को प्रभावित गांवों में चिकित्सा दल भेजकर लोगों की जांच करनी पड़ी। नकली शराब की बोतलों और उनके स्रोत की जांच के साथ यह भी देखा जा रहा है कि अवैध शराब का नेटवर्क कितने गांवों और कितने इलाकों तक फैला हुआ था। यदि जांच में अंतरराज्यीय आपूर्ति की पुष्टि होती है तो यह मामला केवल स्थानीय स्तर पर अवैध शराब बेचने का नहीं, बल्कि एक बड़े नेटवर्क की ओर संकेत करेगा। सागर की घटना कोई अकेला मामला नहीं है। वर्ष 2026 में देश के कई हिस्सों से जहरीली या मिलावटी शराब से मौतों की खबरें सामने आई हैं। बिहार में मार्च और अप्रैल के दौरान ऐसी घटनाओं ने फिर चिंता बढ़ाई। मार्च में सारण जिले में संदिग्ध जहरीली शराब के सेवन के बाद पांच लोगों की मौत की खबर सामने आई और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि प्रशासन ने कुछ मौतों के कारणों पर अलग राय रखी थी, लेकिन परिजनों और स्थानीय लोगों ने शराब सेवन को मौतों से जोड़ा था।

इसके बाद अप्रैल में पूर्वी चंपारण में मिलावटी शराब से मौतों का मामला सामने आया। शुरुआती तौर पर चार-पांच मौतों की जानकारी सामने आई, लेकिन बाद में मृतकों की संख्या सात तक पहुंची। कई लोगों की हालत गंभीर हुई और कुछ मरीजों की आंखों की रोशनी जाने की बात भी सामने आई। मई में बिहार सरकार ने इस मामले में आबकारी विभाग के 14 कर्मचारियों को निलंबित किया। जांच में विभागीय स्तर पर लापरवाही के आरोप भी सामने आए। बिहार की तस्वीर इसलिए और चिंताजनक है क्योंकि राज्य में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाया है। मार्च 2026 में पुलिस की ओर से बताया गया था कि 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से राज्य में जहरीली शराब के सेवन से

354 लोगों की मौत दर्ज की जा चुकी थी। इसका अर्थ साफ है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। कानून के प्रभावी पालन, अवैध नेटवर्क पर लगातार निगरानी और स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी तय किए बिना समस्या का समाधान संभव नहीं है।

महाराष्ट्र में भी मई 2026 में पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ क्षेत्र में जहरीली शराब ने कई परिवारों को तबाह कर दिया। अलग-अलग चरणों में सामने आए आंकड़ों में मौतों की संख्या बढ़ती गई और जून की शुरुआत में महाराष्ट्र सीआईडी ने 20 मौतों को मेथनॉल मिले अवैध शराब से जुड़ा बताया। जांच में अवैध शराब के पीछे आपूर्ति नेटवर्क और जहरीले रसायन की सप्लाई की पड़ताल की गई। इस घटना के बाद पुलिस और आबकारी विभाग के कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई। गुजरात में अगस्त 2026 में भावनगर जिले में जहरीली शराब की घटना ने चिंता बढ़ाई। गुजरात में शराबबंदी लागू होने के बावजूद कथित मिलावटी शराब के सेवन से कई लोग प्रभावित हुए। अगस्त 22 तक मृतकों की संख्या नौ पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई थी, जबकि कई लोग अस्पतालों में उपचार करा रहे थे। जांच में शराब में अत्यंत जहरीले मेथनॉल की मौजूदगी सामने आई। पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और अवैध शराब की आपूर्ति तथा उसके निर्माण की पूरी श्रृंखला की जांच शुरू की। इन घटनाओं को केवल अलग-अलग राज्यों की स्थानीय घटनाएं मानकर छोड़ देना समस्या को छोटा करके देखना होगा। अलग-अलग मामलों में भले ही परिस्थितियां अलग हों, लेकिन एक समान तस्वीर सामने आती है। कहीं अवैध शराब की बिक्री होती है, कहीं नकली बोतलों में शराब भरकर उसे असली जैसा दिखाया जाता है और कहीं जहरीले रसायनों के कारण शराब जानलेवा बन जाती है। जब तक इस पूरी आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक केवल एक दुकान सील करने या कुछ लोगों को गिरफ्तार करने से समस्या समाप्त नहीं होगी। सागर में अधिकारियों के निलंबन और शराब दुकानों को सील किए जाने की कार्रवाई बताती है कि प्रशासन घटना के बाद तेजी दिखा सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि ऐसी कार्रवाई घटना से पहले क्यों नहीं हो पाती। अवैध शराब के कारोबार को रोकने की जिम्मेदारी केवल पुलिस की नहीं है। आबकारी विभाग, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और खुफिया तंत्र के बीच लगातार समन्वय जरूरी है। अवैध शराब का नेटवर्क अक्सर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। इसके पीछे निर्माण, परिवहन, वितरण और बिक्री की अलग-अलग कड़ियां हो सकती हैं। इसलिए किसी घटना के बाद केवल स्थानीय विक्रेता तक पहुंचना पर्याप्त नहीं होना चाहिए। जांच को उस पूरे नेटवर्क तक पहुंचना चाहिए जहां से जहरीली या नकली शराब तैयार होकर अलग-अलग इलाकों तक पहुंचती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आम लोगों को जागरूक किया जाए। सस्ती शराब के लालच में या असली समझकर संदिग्ध शराब पी लेना जानलेवा हो सकता है। किसी व्यक्ति को शराब सेवन के बाद अचानक उल्टी, चक्कर, दृष्टि में परेशानी, असामान्य कमजोरी या गंभीर तबीयत खराब होने जैसी समस्या हो तो इसे सामान्य न मानकर तत्काल चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। जहरीले पदार्थ से होने वाली विषाक्तता में समय पर उपचार जीवन बचाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। जहरीली शराब की हर घटना के बाद आंकड़े सामने आते हैं।इतने लोगों की मौत, इतने अस्पताल में भर्ती, इतने गंभीर और इतने गिरफ्तार। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे की मानवीय कहानी कहीं अधिक भयावह है। एक व्यक्ति की मौत का अर्थ केवल एक संख्या का बढ़ जाना नहीं है। उसका अर्थ है परिवार की आय का खत्म होना, बच्चों की पढ़ाई पर संकट, बुजुर्ग माता-पिता का सहारा छिनना और वर्षों तक चलने वाला आर्थिक तथा मानसिक संघर्ष। इसीलिए जहरीली शराब को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मानना पर्याप्त नहीं होगा। यह सामाजिक, स्वास्थ्य और प्रशासनिक समस्या भी है। सरकारों को अवैध शराब के खिलाफ ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें किसी घटना के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से ही संभावित नेटवर्क की पहचान हो सके।

विचार

भाषाई पुनर्गठनः विविधता को स्वीकार कर मजबूत हुई भारतीय एकता

डॉ. सत्यवान सौरभ

स्वतंत्रता के समय भारत के सामने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता को स्थायी बनाने की चुनौती नहीं थी, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण भी करना था जिसमें भाषा, संस्कृति, परंपरा और क्षेत्रीय पहचान की असाधारण विविधता के बावजूद राष्ट्रीय एकता कायम रहे। ब्रिटिश शासन से विरासत में मिली प्रांतीय सीमाएँ प्रशासनिक सुविधा और औपनिवेशिक हितों के अनुरूप थीं। इनमें अनेक क्षेत्रों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया था। इसलिए स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग स्वाभाविक रूप से उठी। हालाँकि शुरुआती दौर में राष्ट्रीय नेतृत्व भाषाई राज्यों को लेकर आशंकित था। विभाजन की त्रासदी अभी ताजा थी और यह भय था कि यदि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया तो क्षेत्रीय पहचान राष्ट्रीय पहचान पर हावी हो सकती है। किंतु भारतीय लोकतंत्र की विशेषता यही रही कि उसने इन आकांक्षाओं को दबाने के बजाय संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से समायोजित करने का रास्ता चुना। समय ने सिद्ध किया कि भाषाई पहचान को सम्मान देना भारत की एकता के लिए खतरा नहीं, बल्कि उसकी मजबूती का आधार बन सकता है। भाषाई पहचान की राजनीतिक स्वीकार्यता स्वतंत्रता से पहले ही दिखाई देने लगी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रांतीय संगठनों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया था। इसका उद्देश्य यह था कि जनता से संवाद उनकी भाषा और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों में बेहतर ढंग से हो सके। लेकिन स्वतंत्रता और विभाजन के बाद परिस्थितियाँ बदल गईं। राष्ट्रीय नेतृत्व तत्काल किसी बड़े क्षेत्रीय पुनर्गठन के पक्ष में नहीं था।

1948 में गठित धार आयोग ने तत्काल भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा नहीं की। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की सदस्यता वाली जेवीपी समिति ने भी 1949 में राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक स्थिरता और नवगठित राष्ट्र की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उस समय यह सावधानी समझ में आती थी, क्योंकि देश राजनीतिक संक्रमण और सामाजिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। लेकिन जन आकांक्षाओं को अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता था। आंध्र क्षेत्र में तेलुगु भाषी जनता के लिए अलग राज्य की मांग तेज होती गई। पोट्टि श्रीरामुलु के 1952 के आमरण अनशन और उनकी मृत्यु ने इस आंदोलन को निर्णायक मोड़ दिया। व्यापक जनदबाव के बाद 1953 में आंध्र राज्य का गठन हुआ। यह घटना केवल एक राज्य के निर्माण तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने देश के अन्य हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को गति दी। इसके बाद सरकार ने समस्या का व्यापक और संस्थागत समाधान खोजने का प्रयास किया। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी अध्यक्षता फज़ल अली ने की, ने भाषाई और सांस्कृतिक आकांक्षाओं के साथ-साथ प्रशासनिक, आर्थिक तथा भौगोलिक व्यवहार्यता पर भी विचार किया। आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम तथा संविधान का सातवाँ संशोधन लागू हुआ। इसके परिणामस्वरूप भारत के प्रशासनिक मानचित्र में व्यापक बदलाव आया और 14 राज्यों तथा छह केंद्रशासित प्रदेशों की व्यवस्था अस्तित्व में आई। भाषाई राज्यों का सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि उन्होंने क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय पहचान के बीच टकराव को कम किया। जब किसी समुदाय को अपनी भाषा, संस्कृति और स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप प्रशासनिक पहचान मिली तो अलगाव की भावना कमजोर हुई। लोगों को यह विश्वास मिला कि भारतीय संघ उनकी विशिष्ट पहचान को समाप्त करने के बजाय उसका सम्मान करता है। भाषाई पुनर्गठन का दूसरा महत्वपूर्ण लाभ प्रशासनिक स्तर पर दिखाई दिया। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शासन-प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता ने राज्य और नागरिक के बीच दूरी कम की। लोकतंत्र तभी प्रभावी होता है जब नागरिक शासन की भाषा और प्रक्रिया को समझ सके। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशासन ने सामान्य नागरिकों की भागीदारी को अधिक सहज बनाया। इस व्यवस्था ने लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को भी व्यापक बनाया। स्थानीय भाषा बोलने वाले राजनीतिक नेतृत्व को राज्य स्तर पर उभरने का अवसर मिला। इससे राजनीति अधिक जनसरोकारों से जुड़ी और विभिन्न क्षेत्रों की समस्याएँ राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनीं। भाषाई राज्यों ने यह भी सिद्ध किया कि संघीय व्यवस्था में अलग-अलग क्षेत्रीय पहचानें राष्ट्रीय एकता के साथ सह-अस्तित्व रख सकती हैं। भारत का पुनर्गठन 1956 पर समाप्त नहीं हुआ। बदलती राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार राज्यों की सीमाओं में आगे भी परिवर्तन हुए। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन तथा 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के साथ हरियाणा का निर्माण इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि भारतीय संघ कोई स्थिर और अपरिवर्तनीय प्रशासनिक ढाँचा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप स्वयं को ढालने वाली व्यवस्था है।

एक नजर

सारण में बाढ़ पीड़ितों के लिए संचालित कम्युनिटी किचन का जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण

सारण। जिले में बाढ़ की विभीषणता और राहत कार्यों की जमीनी हकीकत का जायजा लेने के उद्देश्य से जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव तथा वरीय पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार ने संयुक्त रूप से सदर अनुमंडल के रिविलगंज अंचल अंतर्गत जान टोला में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए संचालित सामुदायिक किचन की व्यवस्थाओं का गहन मुआयना किया तथा घटते जल स्तर का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने रिविलगंज अंचलाधिकारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जलस्तर पूरी तरह कम होने के उपरांत त्वरित गति से चूना, ब्लीचिंग पाउडर आदि का व्यापक छिड़काव सुनिश्चित किया जाए, ताकि महामारी जनित बीमारियों से प्रभावी बचाव हो सके। जिले के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापित और जरूरतमंदों के लिए राहत कार्य पूरी मुस्तैदी से चलाए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को समय पर पौष्टिक व गर्म भोजन मिल रहा है, जिससे आपदा पीड़ितों को काफी राहत महसूस हो रही है। जिला प्रशासन की पूरी टीम स्थिति पर निरंतर पैनी नजर बनाए हुए है।

छपरा जंक्शन पर शराब के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

सारण। छपरा जंक्शन के पूर्वी यार्ड में रेलवे सुरक्षा बल, सीआईबी और राजकीय रेलवे पुलिस की संयुक्त टीम ने आज कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ तीन संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान इनके पिट्ठू और ट्रॉली बैग से कुल 24.66 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 26,430 रुपये है। बरामद शराब में विभिन्न ब्रांड 61 बोतलें जिनमें 24 बोतल 750 एम एल तथा 37 बोतल 180 एम एल शामिल हैं। गिरफ्तार तस्करों की पहचान निखिल कुमार महिषौर, वैशाली निवासी निखिल कुमार, कदम कुआं पटना निवासी पंकज कुमार एवं जंदाहा पटना निवासी अंकित कुमार के रूप में हुई है। इस कारवाई को अंजाम देने वाली टीम में आरपीएफ छपरा जं. के उपनिरीक्षक विशाल, सीआईबी के एएसआई बृज सुंदर कुमार, हेड कांस्टेबल राम सूरत यादव, आरपीएफ कर्मी जितेंद्र कुमार व राजनाथ यादव, तथा जीआरपी के एएसआई शैलेश कुमार व सिपाही अनुज कुमार शामिल रहे। जीआरपी छपरा ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

मौनिया बाबा राजकीय मेला को लेकर डीएम-एसपी ने कसी कमर, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर जोर

सीवान। उत्तर बिहार के प्रसिद्ध मौनिया बाबा राजकीय मेला को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को डीएवी पब्लिक स्कूल के सभागार में डीएम विजय प्रकाश मीणा और एसपी भारती सोनी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मेला की तैयारियों की समीक्षा की और सुरक्षा, यातायात तथा भीड़ नियंत्रण को लेकर कई अहम निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि मेला के दौरान अखाड़ों के निर्धारित समय का हर हाल में पालन कराया जाए। जिन अधिकारियों व कर्मियों की प्रतिनियुक्ति अखाड़ों के साथ की गयी है, वे पूरे समय अखाड़े के साथ रहकर स्थिति पर नजर बनाए रखें। किसी भी तरह की सूचना मिलने पर तत्काल उसका समाधान किया जाए। उन्होंने मेला क्षेत्र में लगातार सीसीटीवी निगरानी और वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया। साथ ही अधिकारियों को अपनी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखने को कहा। डीएम ने मेला परिसर और प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त बैरिकेडिंग कराने तथा श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए निर्धारित स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यातायात को सुचारु रखने के लिए प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती और विशेष निगरानी रखने को कहा गया। एसपी भारती सोनी ने पुलिस अधिकारियों को लगातार गश्त करने, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त बल तैनात करने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने मेला के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को पूरी तरह सतर्क रहने को कहा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्गों और पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करने की अपील की है। बैठक में एडीएम प्रमोद कुमार, एसडीओ अनीता सिन्हा, एसडीओपी अमन, डीसीएलआर अमन आनंद, अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. सुमीत कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान : संजय सरावगी

पटना,एजेंसी। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आज प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और बिहार में एक माह तक सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों के केंद्र में सेवा, समाज के सभी वर्गों का कल्याण और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प रहेगा। संजय सरावगी ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला था और 7 अक्टूबर 2026 को उनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे एकमात्र नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने अपने जीवन को तपस्या, संकल्प को अटूट और सत्ता को जनता की सेवा का माध्यम बनाया है। राष्ट्र प्रथम और अंत्योदय की भावना से उनकी सरकार ने गरीब, युवा, महिला, किसान, श्रमिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जनधन योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों के खातों में पहुंचा। उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, नल से जल, आयुष्मान भारत, पीएम किसान और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं ने गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव लाया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अनुच्छेद 370 हटाना, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन गंगा जैसे फैसलों ने भारत की वैश्विक छवि को मजबूत किया। कोरोना महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन विकसित की और दुनिया के अनेक देशों की सहायता की। आज वैश्विक संकट के बीच भारत मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी अधिक है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। संजय सरावगी ने कहा कि बिहार में भी केंद्र सरकार के सहयोग से पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट, नालंदा विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम हुआ है। मेडिकल शिक्षा में भी बड़ा विस्तार हुआ है। 2014 में देश में करीब 387 मेडिकल कॉलेज थे, जो बढ़कर करीब 818 हो गए हैं। एमबीबीएस सीटें 51,348 से बढ़कर करीब 1.29 लाख तथा मेडिकल पीजी सीटें 31,185 से बढ़कर करीब 82 हजार हो गई हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या भी 760 से बढ़कर 1,289 हुई है। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को अभियान की शुरुआत आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम से होगी। शाम सात बजे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी अपने घरों में दीप जलाकर प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। युवा मोर्चा पूरे राज्य में रक्तदान शिविर आयोजित करेगा। प्रधानमंत्री आवास, राशन, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों, डेयरी, पटरी, ठेला और लघु उद्योग से जुड़े लोगों से भी दीप प्रज्वलित करने की अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि सेवा चित्र कार्यक्रम के तहत 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्कूलों और महाविद्यालयों में चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिताएं होंगी। प्रधानमंत्री की जनसेवा, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत विषयों पर प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी तथा प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र और पुरस्कार दिए जाएंगे।

राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते से मुकदमों का होगा त्वरित और निःशुल्क निपटारा

कटिहार। व्यवहार न्यायालय परिसर में आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) ने सघन जागरूकता अभियान शुरू किया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष रणवीर सिंह तथा सिविल जज (वरीय कोटि)-सह-सचिव कमलेश कुमार देव के निर्देशानुसार पारा विधिक स्वयंसेवक (पीएलवी) क्षेत्र में उतरकर आम जनता को लोक अदालत की सुविधाओं और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। अभियान के तहत पीएलवी पवन कुमार ने कटिहार कोर्ट परिसर सहित शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर नागरिकों को बताया कि पैसे के अभाव में न्याय से वंचित लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार निःशुल्क कानूनी सलाह, सहायता और सरकारी अधिवक्ता उपलब्ध कराता है।

आगामी लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, फौजदारी व दीवानी वाद, बैंक ऋण, बिजली व पानी बिल विवाद, पारिवारिक व वैवाहिक मामले, भूमि विवाद, मोटर दुर्घटना दावा और श्रम विवाद जैसे सुलह योग्य मामलों का त्वरित निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से कराया जाएगा। पवन कुमार ने जानकारी दी कि लोक अदालत में वादों के निस्तारण पर किसी भी प्रकार की कोर्ट फीस या वकील का शुल्क नहीं लगता है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे अपने वर्षों से लंबित मुकदमों और नए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस निःशुल्क न्यायिक सुविधा का लाभ उठाएं। इस जागरूकता अभियान के दौरान पारा विधिक स्वयंसेवक अविनाश कुमार और सचिन कुमार भी उपस्थित रहे।

नीतीश कुमार ने पटना जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों का लिया जायजा, उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री से की चर्चा

पटना। जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने मंगलवार को फिर पटना जिले के बाढ़ प्रभावित एवं जलजमाव वाले विभिन्न गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नथ्थाचक, विक्रमपुर, फतुहा, डुमरी, भिखुआ, जनार्दनपुर, मछरीयावां, मालबीघा, शिवचक, मुड़ेरा, नयका रोड, सिकन्दरपुर, मकसुदपुर, मुस्तफापुर, मसाढ़ी, जमालपुर, सैदनपुर, बेलदारीचक, लखना, निहालचक, मदारपुर, डुमरीपुल, पुनपुन, अकौना, सतीशनगर, मनौरा, गोपालपुर, चिनिया टोला, चीहुट, देवेन्द्र नगर, परसा एवं दीनदयाल नगर का दौरा कर जलस्तर को देखा और स्थानीय लोगों से सरकार द्वारा मिल रही सहायता की जानकारी ली। पुनपुन समेत अन्य सभी इलाके के जलस्तर की स्थिति देखकर नीतीश कुमार ने उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी को बुलाया और उनसे बाढ़ प्रभावित तमाम इलाकों की अद्यतन जानकारी ली तथा सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मंत्री विजय चौधरी से कहा कि संबंधित अधिकारियों को विभाग व सरकार की ओर से पूरी तत्परता बरतने का निर्देश रहे और राहत एवं बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग की समुचित व्यवस्था हो। नीतीश कुमार ने कहा कि कोई सरकार कितनी अच्छी है, इसका पता इस बात से लगता है कि आपदा के समय अपनी जनता के साथ वो कितनी संवेदना और कैसे दायित्वबोध से खड़ी है। पिछले दो दशकों में एनडीए सरकार ने इस दिशा में जो मानक स्थापित किया है, उसको हमेशा ध्यान में रखें। इस दौरान बिहार विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन सर्राफ उपस्थित रहे।

कटाव और बाढ़ पीड़ितों तक नहीं पहुँच रही पर्याप्त सरकारी राहत, प्रशासन की लापरवाही से टूटे तटबंध और सड़केंः कांग्रेस

भागलपुर। भागलपुर के पूर्व विधायक एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य अजीत शर्मा के निर्देश पर मंगलवार को कांग्रेस के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने नवगछिया अनुमंडल के कटाव-पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने बाढ़ और कटाव से प्रभावित विभिन्न स्थलों का जायजा लेने के साथ ही वहाँ प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों की जमीनी हकीकत जानी।

इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। दौरे के बाद प्रतिनिधिमंडल ने सरकार और प्रशासनिक दावों की पोल खोलते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर पीड़ितों के बीच पर्याप्त राहत कार्य नहीं चल रहा है। बाढ़ पीड़ितों को जरूरत के मुताबिक सरकारी सुविधाएं और सहायता सामग्री अब तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है, जिससे प्रभावित परिवारों में भारी आक्रोश और निराशा है। कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समय रहते प्रशासनिक मुस्तैदी दिखाई गई होती, तो न तो राघोपुर तटबंध टूटता और न ही सैदपुर सकुटिया बाजार को जोड़ने वाली मुख्य सड़क कटती। प्रशासन की इसी निष्क्रियता का खामियाजा आज हजारों गरीब और लाचार ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। इस दौरे और निरीक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि डॉ. अभय आनंद, सोइन अंसारी, इंटक अध्यक्ष इंजीनियर रवि कुमार, शीतल प्रसाद सिंह निषाद, राजीव चौधरी, मोहम्मद मोईजुद्दीन सहित दर्जनों वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से मांग की है कि युद्धस्तर पर राहत कार्य चलाकर पीड़ितों को अविलंब सहायता पहुंचाई जाए और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत कराई जाए।

'अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे सरकारी योजनाओं का लाभ, कोताही बर्दाश्त नहीं': डीएम

कटिहार,एजेंसी। जमीनी स्तर पर प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय करने और पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कटिहार जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय समिति की जिला स्तरीय बैठक पंचायत सरकार भवन, भवाड़ा के सभागार में आयोजित की गई। उच्च स्तरीय जिला बैठक को पंचायत स्तर पर ले जाने की इस अभिनव पहल से जहां ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासनिक पारदर्शिता और जागरूकता बढ़ेगी, वहीं पंचायत सरकार भवनों के समुचित उपयोग व रखरखाव में भी सुधार होगा। जिलाधिकारी के इस नवाचार की प्रशासनिक और जन हलकों में व्यापक सराहना की जा रही है।

बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि जनहित से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तय समय सीमा के भीतर निष्पादित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना अनिवार्य है और दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की शिथिलता या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा के दौरान मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल-जीवन-हरियाली तथा सात निश्चय योजना की प्रगति का जायजा लिया गया और लक्ष्य से पीछे चल रहे प्रखंडों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने दाखिल-खारिज, परिमार्जन और अतिक्रमण वादों का त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी योजनाओं के लिए भू-अर्जन का कार्य तेज करने और जिले के सभी विद्यालयों की भूमि का अनिवार्य रूप से दाखिल-खारिज कराने पर बल दिया। स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के क्रम में अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, एएनएम की शत-प्रतिशत उपस्थिति, विद्यालयों में शिक्षकों की समयबद्ध उपस्थिति और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण कार्य में तेजी लाने और सभी विभागों को आपसी समन्वय से विकास कार्यों को गति देने को कहा गया। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार स्थलीय भ्रमण कर आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने की हिदायत दी। बैठक में अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी समेत सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे, जबकि सभी प्रखंडों के बीडीओ व सीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

भागलपुर में नशे के सौदागरों पर पुलिस का बड़ा प्रहार, 17.49 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

भागलपुर। नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध बिक्री के खिलाफ बिहार पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिटी एसपी अतुलेश झा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बताया कि ईशाकचक थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को भारी मात्रा में ब्राउन शुगर के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 17.49 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है।

गिरफ्तार तस्करों में मोनू कुमार, मुकेश कुमार और गुरुदेव कुमार शामिल है। मौके से एक डिजिटल तराजू और 4,300 रुपया नकद भी बरामद किए गए हैं। सिटी एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, बरामद किया गया नशीला पदार्थ शहर में बिक्री और युवाओं को सप्लाई करने के उद्देश्य से रखा गया था। पुलिस अब आरोपियों को रिमांड पर लेकर यह पता लगाने में जुटी है कि इस खेप की डिलीवरी कहां से हुई थी और इसके पीछे किस बड़े सप्लायर या सिंडिकेट का हाथ है। पूछताछ के आधार पर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सिटी एसपी ने सख्त लहजे में कहा कि खासकर युवाओं को नशे की गर्त में धकेलने वाले अवैध कारोबारियों पर पुलिस की पैनी नजर है। इस सफल कार्रवाई के बाद से इलाके के नशा माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए ब्राउन शुगर और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ यह विशेष अभियान आगे भी पूरी कड़ाई से जारी रहेगा। फिलहाल, तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम रवाना, लॉस एंजिल्स ओलंपिक का सीधा टिकट लक्ष्य

बेंगलुरु, एजेंसी। एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स 2026 में ऐतिहासिक पांचवां स्थान हासिल करने के बाद भारतीय महिला टीम मंगलवार को जापान के लिए रवाना हो गई। टीम का लक्ष्य एशियाई खेल आइची-नागोया 2026 में स्वर्ण पदक जीतने के साथ लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालीफाई करना है। टीम की कप्तानी सलीमा टेटे कर रही हैं, जबकि मुख्य कोच की जिम्मेदारी सजॉर्ड मारिजने संभाल रहे हैं। मारिजने की वापसी के बाद भारतीय महिला टीम ने फिटनेस, टीम के बीच तालमेल और मजबूत सामूहिक पहचान पर विशेष ध्यान दिया है। उनके मार्गदर्शन में भारत ने 2026 की शुरुआत एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप क्वालीफायर में रजत पदक के साथ की। टीम फाइनल तक अजेय रही और इटली को सेमीफाइनल में 1-0 से हराकर विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया। इसके बाद भारत ने ऑकलैंड में एफआईएच महिला हॉकी नेशंस कप में शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने पूल चरण में अमेरिका, जापान और उरुग्वे को हराया। सेमीफाइनल में चिली को 6-0 से मात देने के बाद फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने अगले सत्र की एफआईएच महिला हॉकी प्रो लीग में भी पदोन्नति हासिल की।

विश्व कप में भी भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और पांचवें स्थान पर रही, जो 1974 के पहले विश्व कप के बाद उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत को पूरे टूर्नामेंट में केवल एक हार मिली। टीम ने चीन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी ऊंची रैंकिंग वाली टीमों के खिलाफ ड्रॉ खेला, जबकि दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से हराया। भारत ने विश्व कप का समापन विश्व नंबर पांच जर्मनी के खिलाफ 3-1 की जीत से किया। अब भारतीय टीम की नजर एशियाई खेलों पर है, जहां दांव और भी बड़ा है। एफआईएच के लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक क्वालीफिकेशन नियमों के अनुसार, महिला हॉकी प्रतियोगिता में सबसे ऊंचे स्थान पर रहने वाली पात्र टीम को ओलंपिक कोटा स्थान मिलेगा, बशर्ते वह किसी अन्य माध्यम से पहले ही क्वालीफाई न कर चुकी हो। ऐसे में भारत के लिए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतना सीधे ओलंपिक टिकट हासिल करने का रास्ता होगा।

भारत को पूल बी में जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और उज्बेकिस्तान के साथ रखा गया है। भारतीय टीम 20 सितंबर को उज्बेकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद 21 सितंबर को इंडोनेशिया, 23 सितंबर को थाईलैंड, 25 सितंबर को जापान और 27 सितंबर को सिंगापुर से मुकाबला होगा। नॉकआउट चरण 30 सितंबर से शुरू होगा और इसी दिन सेमीफाइनल भी खेले जाएंगे। स्वर्ण पदक का मुकाबला 2 अक्टूबर को होगा। कप्तान सलीमा टेटे ने कहा कि टीम हालिया सफलताओं से आत्मविश्वास से भरी है, लेकिन एशियाई खेलों में हर मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। उन्होंने कहा, 'हम एशियाई खेलों में काफी आत्मविश्वास के साथ जा रहे हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हर टूर्नामेंट एक नई चुनौती लेकर आता है। नेशंस कप और विश्व कप ने हमें यह विश्वास दिया है कि हम एक टीम के रूप में क्या हासिल कर सकते हैं और अब हमारा ध्यान उससे एक कदम आगे बढ़ने पर है। हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है—हम स्वर्ण पदक के लिए पूरी ताकत से लड़ना चाहते हैं और लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए सीधे क्वालीफाई करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इसके लिए निरंतरता, अनुशासन और हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ देना जरूरी होगा और एक टीम के रूप में हम इस चुनौती के लिए तैयार हैं। एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा प्रतिभाओं का भी अच्छा मिश्रण है। टीम में दो गोलकीपर सविता और बिचु देवी खरिबाम, पांच डिफेंडर इशिका चौधरी, सुशीला चानू पुखरामबम, लालथांतलुआंगी, ज्योति और शिल्पी डबास शामिल हैं। मिडफील्ड में निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिता टोप्पो, कप्तान सलीमा टेटे, नेहा और दीपिका सोरेंग हैं। अग्रिम पंक्ति में लालरेमसियामी, रुतुजा दादासो पिसाल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर और ब्यूटी डुंगडुंग को जगह मिली है। नेशंस कप खिताब और पांच दशक से अधिक समय बाद विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद भारतीय महिला टीम के पास एशियाई खेलों में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने का सुनहरा मौका है।

एक नजर

गिल के अर्धशतक पर भारी पड़ी अभिषेक की तूफानी पारी

मोहाली। अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेलकर शुभमन गिल के अर्धशतक की चमक फीकी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे अमृतसर सोर्मस ने शेर-ए-पंजाब टी20 लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में फाजिल्का फाल्कन्स पर चार विकेट से जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखा। फाजिल्का फाल्कन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 191 रन बनाए। उसने 20 रन के अंदर दो विकेट गंवा दिए थे लेकिन कप्तान शुभमन गिल और प्रांशु प्रताप ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़े। गिल ने 35 गेंदों में 67 रन बनाए। गिल के आउट होने के बाद प्रांशु (33 गेंदों में 40 रन) और सनवीर सिंह (21 गेंदों में 40 रन) ने टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। अमृतसर सोर्मस ने शानदार शुरुआत की। अभिषेक और सहज धवन ने पहले विकेट के लिए 79 रन जोड़े। अभिषेक ने ने 15 गेंदों में 49 रन की तेज पारी खेली। लेकिन अमृतसर ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवा दिए। इससे उसका स्कोर पांच विकेट पर 152 रन हो गया। राहुल कुमार ने हालांकि 35 गेंद पर नाबाद 53 रन बनाकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया।

रोहित यादव के स्थान पर आर्यन सवसानी और तन्मय बलोदा भारत अंडर-19 टीम में शामिल

नई दिल्ली। सौराष्ट्र के आर्यन सवसानी और हरियाणा के तन्मय बलोदा को उम्र में धोखाधड़ी के मामले में बाहर किए गए रोहित यादव के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस महीने के आखिर में होने वाली श्रृंखला के लिए मंगलवार को भारत की अंडर-19 टीम में शामिल किया गया। रोहित को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय और लंबी अवधि के प्रारूप के लिए दोनों टीम में शामिल किया गया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने उन पर कथित तौर पर अपनी उम्र गलत बताने के आरोप में दो साल का प्रतिबंध लगा दिया है। बीसीसीआई ने कहा कि सवसानी और बलोदा क्रमश: एकदिवसीय और बहुदिवसीय भारतीय टीमों में यादव की जगह लेंगे। बीसीसीआई ने बताया, ''जूनियर चयन समिति ने सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के आर्यन सवसानी को रोहित यादव के स्थान पर भारत की अंडर-19 वनडे टीम में, जबकि हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के तन्मय बलोदा को बहुदिवसीय टीम में शामिल किया है। भारत अंडर-19 टीम राजकोट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन एकदिवसीय मैच और पहला बहुदिवसीय मैच खेलेगी, जबकि दूसरा बहुदिवसीय मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। तीनों एकदिवसीय मैच क्रमश: 18, 21 और 23 सितंबर को, जबकि दो बहुदिवसीय मैच 27 से 30 सितंबर और पांच से आठ अक्टूबर को खेले जाएंगे।

टीम इस प्रकार हैं:

एकदिवसीय मैचों के लिए: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), यशबर्धन चौहान (उपकप्तान), रजत बघेल (विकेटकीपर), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), वी. यशवीर, शाविन विनोद, मोहित उलवा, चिगुरुपति वेंकट, काव्या पटेल, आर्यन सवसानी।

बहुदिवसीय मैचों के लिए: यशबर्धन चौहान (कप्तान), लक्ष्य रायचंदानी (उप-कप्तान), सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, मनल चौहान, कुश पटेल, मानव कृष्णा (विकेटकीपर), अभिप्राय विश्वास (विकेटकीपर), इशान ओम, अयान अकरम, प्रणव राघवेंद्र, प्रियांशु सिंह, मोहित उलवा, आर्यन यादव, तन्मय बलोदा।

महिला जूनियर एशिया कप: जापान को 7-0 से हराकर भारत क्वार्टर फाइनल में

मोकी (चीन)। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने एशिया कप में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए मंगलवार को यहां अपने तीसरे एलीट पूल मैच में जापान को 7-0 से करारी शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। इस जीत से भारत के तीन मैचों में नौ अंक हो गए हैं और वह अभी एलीट पूल में शीर्ष पर है। भारत बुधवार को पूल के अपने आखिरी मैच में चीन का सामना करेगा, जिससे पूल में शीर्ष स्थान पर रहने वाली टीम का निर्धारण होगा। चीन के अभी दो मैचों में छह अंक हैं। कोरिया के खिलाफ 4-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने और फिर मलेशिया के खिलाफ 11-1 से बड़ी जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम ने जापान के खिलाफ मुकाबले में अपनी आक्रामक लय को बरकरार रखा और शुरुआत से ही खेल पर नियंत्रण बना लिया। भारत के शुरुआती दबाव का फायदा उसे पांचवें मिनट में मिला जब कृष्णा शर्मा ने गोल दागकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। भारत को नौवें मिनट में जापानी डिफेंडर के सर्कल के अंदर फाउल करने से पेनल्टी मिली। सुप्रिया ने इसे गोल में बदलकर भारत को 2-0 से आगे कर दिया। भारत ने अपना दबदबा बनाए रखते हुए पहले क्वार्टर के आखिरी क्षणों में तीसरा गोल दागा। पूर्णिमा यादव ने 14वें मिनट में मैदानी गोल किया जिससे भारत ने पहले क्वार्टर में 3-0 की अच्छी बढ़त हासिल कर ली। दूसरे क्वार्टर में जापान ने अधिक आक्रामक रुख अपनाया और मैच में वापसी की कोशिश की। भारत ने भी अपनी बढ़त मजबूत करने की कोशिश की लेकिन दोनों में से कोई भी टीम इस क्वार्टर में गोल नहीं कर सकी। इस तरह से भारत हाफटाइम तक 3-0 से आगे था। जापान ने तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में भी आक्रमण को प्राथमिकता दी लेकिन भारतीय रक्षापंक्ति के सामने उसकी एक नहीं चली। इसके बाद भारत ने पांच मिनट के भीतर तीन गोल दाग दिए। गीता यादव ने 41वें मिनट में मैदानी गोल दागकर स्कोर 4-0 कर दिया। गीता ने 45वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया। इसके तुरंत बाद पूर्णिमा ने भी अपना दूसरा गोल किया और तीसरे क्वार्टर के अंत तक भारत को 6-0 की बढ़त दिला दी। भारतीय टीम ने अंतिम क्वार्टर में भी अपना आक्रामक रुख बरकरार रखा और 50वें मिनट में सानिका चंद्रकांत माने के गोल से टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत सुनिश्चित की।

मार्क चैपमैन ने न्यूजीलैंड का केंद्रीय अनुबंध छोड़ा, बिग बैश लीग में खेलने का रास्ता साफ

ऑकलैंड। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्क चैपमैन ने 2026-27 सत्र के लिए केंद्रीय अनुबंध से बाहर होने का फैसला किया है। उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ आकस्मिक अनुबंध स्वीकार किया है, जिससे वह बिग बैश लीग में खेलने के लिए उपलब्ध रह सकेंगे। चैपमैन न्यूजीलैंड की आगामी घरेलू श्रृंखला में भारत के खिलाफ खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। उनके अलावा फिन एलन, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिल्न और टिम सीफर्ट भी इसी तरह के आकस्मिक अनुबंध पर हैं। बिग बैश लीग का आगामी सत्र 12 दिसंबर से 26 जनवरी तक खेला जाना है, जो न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलिया दौरे और श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीमित ओवर श्रृंखला के साथ टकरा रहा है।

चैपमैन ने एक आधिकारिक बयान में कहा, 'मैं अपने पूरे करियर के दौरान समर्थन के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट का आभारी हूं। भारत के खिलाफ आगामी श्रृंखला को लेकर हम सभी खिलाड़ी बेहद उत्साहित हैं और मैं उस श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं।' चैपमैन के केंद्रीय अनुबंध से बाहर होने के बाद खाली हुई जगह नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के तेज गेंदबाज मैथ्यू फिशर को मिली है। फिशर को पहली बार न्यूजीलैंड क्रिकेट का केंद्रीय अनुबंध मिला है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य उच्च प्रदर्शन अधिकारी डेरिल गिब्सन ने कहा, 'मैट फिशर के केंद्रीय अनुबंध सूची में आने से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में एक स्थान खाली हुआ है, जिससे उनके विकास को जारी रखने के लिए एक और खिलाड़ी को अनुबंध सूची में शामिल करने का अवसर मिलेगा। मैट ने ब्लैककैप्स के लिए मिले अवसरों में प्रभावित किया है और उनकी तेज गति निश्चित रूप से ऐसी चीज है जिसे हम आगे विकसित करना चाहते हैं। चयन प्रबंधक गेविन लार्सन ने कहा कि आगामी व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए टीम में तेज गेंदबाजी की पर्याप्त गहराई की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'आने वाले व्यस्त क्रिकेट कार्यक्रम में भारत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच शामिल हैं। हमें पता है कि ब्लैककैप्स को सफलता का सर्वश्रेष्ठ मौका देने के लिए तेज गेंदबाजी में अच्छी गहराई की जरूरत होगी। मैट ऐसी तेज गति से गेंदबाजी कर सकते हैं, जो किसी भी टीम के संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्हें केंद्रीय अनुबंध सूची में शामिल कर हम उत्साहित हैं। न्यूजीलैंड का घरेलू सत्र भारत के खिलाफ 22 अक्टूबर से शुरू होगा। भारत के खिलाफ 12 मुकाबलों की श्रृंखला में पांच वनडे, पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय और दो टेस्ट मैच शामिल हैं, जो 1 दिसंबर तक चलेगी।

यूएस ओपन: राइबाकिना क्वार्टर फाइनल में, झेंग से होगी भिड़ंत, गॉफ तीन साल बाद अंतिम-8 में

न्यूयॉर्क। कजाकिस्तान की एलेना राइबाकिना ने सोमवार को पूर्व चैंपियन नाओमी ओसाका को सीधे सेटों में हराकर यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। दूसरी वरीय राइबाकिना ने ओसाका को 6-1, 6-4 से हराया। अब उनका सामना चीन की झेंग छिनवेन से होगा। सेमीफाइनल में पहुंचते ही राइबाकिना विश्व नंबर-1 बन जाएंगी। राइबाकिना ने ऑन कोर्ट साक्षात्कार में कहा, 'बेशक मैं नंबर-1 बनना चाहती हूं। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानती जो ऐसा नहीं चाहेगा। निश्चित रूप से यह मेरे लक्ष्यों में से एक है। मैं हर मैच को उसी तरह लेने की कोशिश करती हूं, अपना सर्वश्रेष्ठ देने और अंत तक लड़ने की कोशिश करती हूं। अब अगले मुकाबले में क्या होता है, देखते हैं। झेंग छिनवेन ने आठवीं वरीय इगा श्वियातेक को 7-5, 6-3 से हराकर अंतिम-8 में प्रवेश किया। चीन की 2024 ओलंपिक चैंपियन झेंग लगातार दूसरे मुकाबले में शुरुआती पांच गेम गंवाने के बाद वापसी करने में सफल रहीं।

वह 2021 में एमा राडुकानु के चैंपियन बनने के बाद यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली क्वालीफायर बनीं। इससे पहले झेंग ने मैडिसन कीज के खिलाफ तीसरे सेट में 0-5 से पिछड़ने के बाद लगातार सात गेम जीतकर 1-6, 7-6, 7-5 से मुकाबला अपने नाम किया था। श्वियातेक के खिलाफ भी वह शुरुआती पांच गेम हार गई थीं। झेंग ने कहा, 'मेरा मानना है कि कल 0-5 से वापसी करना किस्मत नहीं थी। मैं बस इतना ही कह सकती हूं। राइबाकिना ने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया था और विश्व नंबर-2 उनकी करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। बुधवार को हारने के बावजूद उनके पास नंबर-1 बनने का मौका रहेगा, बशर्ते आर्यना सबालेंका, कोको गॉफ या जेसिका पेगुला में से कोई भी खिताब न जीते। ओसाका के खिलाफ मुकाबला केवल एक घंटे छह मिनट चला। राइबाकिना ने ऐस के साथ मैच समाप्त किया। इस समय वह महिला टेनिस संघ के पूरे दौरे में सबसे ज्यादा ऐस लगाने वाली खिलाड़ियों में शीर्ष पर हैं। ओसाका, जिन्होंने अपने चार ग्रैंड स्लैम खिताबों में से दो यूएस ओपन में जीते हैं, मुकाबले के दौरान पैर या टखने की समस्या से जूझती नजर आईं। चौथी वरीय कोको गॉफ ने 14वीं वरीय इवा जोविच को 6-1, 6-4 से हराकर तीन साल बाद यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। गॉफ ने 2023 में इसी टूर्नामेंट में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। इसके बाद वह पिछले दो वर्षों में चौथे दौर से आगे नहीं बढ़ सकी थीं। गॉफ के सामने अब फ्रेंच ओपन चैंपियन और पांचवीं वरीय मिर्रा आंद्रीवा की चुनौती होगी। आंद्रीवा ने 24वीं वरीय अनास्तासिया पोटापोवा को 5-7, 6-4, 6-3 से हराया। मुकाबले के अंतिम गेम में पोटापोवा के घुटने में चोट लगने के बाद आंद्रीवा ने उनकी मदद भी की।

लद्दाख में 'एनआईएमएएस' का कारनामा, 23 दिनों में 20 अविजित चोटियों पर फहराया तिरंगा

नई दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स (एनआईएमएएस), दिरांग ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए लद्दाख में 6,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 20 अविजित चोटियों पर सफल पर्वतारोहण अभियान पूरा किया। टीम ने सिर्फ 23 दिनों में इन 20 चोटियों पर पहली बार सफल आरोहण करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

इस उपलब्धि पर रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर लिखा, 'दिरांग स्थित 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स' (एनआईएमएएस) ने अगस्त-सितंबर 2026 के दौरान लद्दाख में 20 ऐसी चोटियों पर पहली बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इतिहास रच दिया है, जिन पर पहले कभी कोई नहीं चढ़ा था, उन्होंने 23 दिनों के रिकॉर्ड समय में इन 20 चोटियों पर पहली बार चढ़ाई पूरी की। यह शानदार उपलब्धि माउंटेनियरिंग, खोज-बीन, अभियान के नेतृत्व और एडवेंचर स्पोर्ट्स में भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है। साथ ही, यह देश के युवाओं को चुनौतियों का सामना करने, भारत के विविध इलाकों को जानने और राष्ट्र-निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। एनआईएमएएस अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरंग में स्थित है, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख संस्थान है। यह देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो जमीन, हवा और पानी से जुड़े एडवेंचर स्पोर्ट्स में प्रशिक्षण और अभियान की गतिविधियां प्रदान करता है।

लद्दाख में एनआईएमएएस का यह अभियान एक बड़ी उपलब्धि है। टीम ने 23 दिनों में 20 ऐसी ऊंची चोटियों पर पहली बार चढ़ाई की, जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था। यह सफलता दिखाती है कि भारत के युवा कठिन परिस्थितियों में भी बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। साथ ही, यह अभियान देश के दूरदराज हिमालई क्षेत्रों में साहसिक खेलों और खोज अभियानों में भारत की बढ़ती क्षमता को भी दर्शाता है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दूरदर्शिता से भी जुड़ी है, जिसमें युवाओं को देश को करीब से जानने, नए क्षेत्रों की खोज करने, फिट रहने और रोमांचक गतिविधियों के जरिए खुद को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया गया है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग में निजी निवेश का रास्ता खोला, मेलबर्न रेनेगेड्स से होगी शुरुआत

मेलबर्न। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने बिग बैश लीग (बीबीएल) में निजी निवेश का रास्ता खोलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत मेलबर्न रेनेगेड्स ऐसा पहला क्लब होगा, जिसके लिए निजी निवेशकों से बोली आमंत्रित की जाएगी। योजना के अनुसार रेनेगेड्स 2027-28 सत्र में नए स्वामित्व के साथ मैदान पर उतर सकता है।

सीए निजी निवेशकों से रेनेगेड्स के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करेगा। इस प्रक्रिया की सफलता के बाद अन्य बिग बैश लीग क्लबों के लिए भी निजी निवेश का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, भविष्य में किसी अन्य क्लब की बिक्री का फैसला संबंधित राज्य सदस्य अपने क्लब और स्थानीय समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष माइक बेयर्ड ने एक आधिकारिक बयान में कहा, 'क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और उसके राज्य सदस्य बिग बैश लीग और महिला बिग बैश लीग में निवेश करने और उन्हें विकसित करने तथा क्रिकेट के हर स्तर के हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिग बैश लीग में निजी निवेश का रास्ता खोलकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खेल के दीर्घकालिक भविष्य को मजबूत और सुरक्षित करने की दिशा में एक सोच-समझकर उठाया गया कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा, 'रेनेगेड्स की बिक्री प्रक्रिया शुरू करना हमारे सदस्यों के लिए स्व-निर्धारण मॉडल में पहला कदम है और यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सीए ने स्पष्ट किया है कि निजी निवेश आने के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के महत्वपूर्ण मामलों पर उसका और उसके राज्य सदस्यों का नियंत्रण बना रहेगा। इनमें अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, खिलाड़ियों की उपलब्धता, बिग बैश लीग और महिला बिग बैश लीग की वेतन सीमा, ब्रांडिंग से जुड़े प्रस्ताव, लाइसेंस के लिए न्यूनतम निर्धारित मूल्य और निवेशकों की मंजूरी शामिल हैं। बेयर्ड ने कहा, 'यह एक महत्वपूर्ण फैसला है, जिसके लिए कई महीनों तक व्यापक विश्लेषण, चर्चा और सहयोग किया गया है। मैं इस प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम मानते हैं कि यह ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के भविष्य को सुरक्षित करने, बिग बैश को मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति बनाए रखने का सबसे बेहतर तरीका है। मेलबर्न रेनेगेड्स की बिक्री प्रक्रिया ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में क्लब स्वामित्व के ढांचे में बड़े बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है। इससे बिग बैश लीग में निजी पूंजी के प्रवेश का रास्ता साफ हो सकता है और आने वाले समय में अन्य क्लब भी इसी मॉडल को अपना सकते हैं।

एक नजर

'ब्रिक्स' शिखर सम्मेलन में भारत के साथ विचार-विमर्श को आगे बढ़ाएंगे: इस्माइल बाघेई

नई दिल्ली,एजेंसी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने मंगलवार को भारत के साथ ईरान के बेहतर संबंधों को जिक्र किया। उन्होंकने बिश्केक में राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ हुई प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा कि भारत के साथ हमारे विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे संबंध हैं। बाघेई ने कहा कि हम 'ब्रिक्स' शिखर सम्मेलन में होने वाली मुलाकात का लाभ उठाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ बातचीत और विचार-विमर्श को आगे बढ़ाएंगे। भारत में ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्सर' पोस्टग में इस्माइल बाघेई के बयान का एक वीडियो साझा किया। इस्माइल बाघेई ने कहा, 'राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने बिश्केक में जिन नेताओं से मुलाकात की, उनमें भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। भारत के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने, ऐतिहासिक और सभ्यतागत रिश्तों पर आधारित हैं और हम भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। उन्होंभने कहा कि भारत शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) और 'ब्रिक्स' दोनों का सदस्य है। यह उन देशों में से एक हैं, जिनके साथ हमारे विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे संबंध हैं। खासकर व्यापार और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में। उन्हों ने बताया कि ईरान और भारत के बीच होने वाली चर्चाओं में आमतौर पर कई मुद्दों पर बात होती है। इनमें चाबहार बंदरगाह भी शामिल है, जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान ईरानी प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी जिक्र किया। बाघेई ने कहा, 'ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से मिलने वाले अवसर का हम निश्चित रूप से उपयोग करेंगे, ताकि आपसी हितों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ बातचीत और विचार-विमर्श को आगे बढ़ाया जा सके। जैसा कि मैंने कहा, भारत के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं।

हवाई द्वीपों की ओर बढ़ा हरिकेन लोवेल, कई इलाकों में चेतावनी जारी, बाढ़-भूस्खलन का खतरा

लॉस एंजिल्स। अमेरिकी नेशनल वेदर सर्विस (एनडब्यू एस) और नेशनल हरिकेन सेंटर (एनएचसी) की ताजा जानकारी के अनुसार, हरिकेन लोवेल पश्चिमी हवाई द्वीपों की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते हवाई के कुछ इलाकों के लिए हरिकेन चेतावनी और ओआहू के लिए ट्रॉपिकल स्टॉर्म चेतावनी जारी की गई है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने एनडब्यू एस होनोलूलू ऑफिस के हवाले से बताया कि काउई, नीहाऊ और उनके आसपास उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की समुद्री सीमाओं के लिए अब हरिकेन चेतावनी लागू कर दी गई है। एनएचसी ने बताया कि लोवेल का केंद्र सोमवार रात और मंगलवार सुबह के बीच निहाऊ के पास या उसके पश्चिम से गुजर सकता है। काउई काउंटी में सोमवार रात से हरिकेन जैसी परिस्थितियां बनने की आशंका है। सोमवार दोपहर से मौसम के हालात बिगड़ने शुरू हो सकते हैं। एनएचसी के अनुसार, पहाड़ी इलाकों और पहाड़ों की हवा वाली तथा दूसरी ढलानों पर तेज झोंकों वाली हवाएं चलने की संभावना है। एनएचसी ने चेतावनी दी है कि हरिकेन लोवेल की वजह से भारी बारिश हो सकती है, जिससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाएगा। खास तौर पर काउई काउंटी और बिग आइलैंड के कुछ हिस्सों में इसका ज्यादा असर पड़ सकता है। एनएचसी ने यह भी चेतावनी दी है कि लोवेल से पैदा होने वाली ऊंची समुद्री लहरें आने वाले कई दिनों तक हवाई के कई द्वीपों में बेहद खतरनाक हालात पैदा कर सकती हैं। तेज लहरों और खतरनाक रिप करंट्स (समुद्र की तेज वापसी वाली धाराओं) से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। हवाई के गवर्नर जोश ग्रीन ने तीन सितंबर को पूरे राज्य के लिए आपातकालीन घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य हरिकेन लोवेल, हरिकेन करिना, ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैरी और हवाई को प्रभावित करने वाले अन्य संभावित तूफानों की तैयारी और उनके असर से निपटने में मदद करना है। इस घोषणा से राज्य और स्थानीय प्रशासन की एजेंसियां जरूरत पड़ने पर अपने कर्मचारियों, उपकरणों और संसाधनों को अधिक तेजी से तैनात कर सकेंगी। हवाई अभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन लाला से हुए नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा है। पिछले महीने हरिकेन लाला ने हवाई में भारी तबाही मचाई थी। द्वीप में लगभग 17,000 बिजली उपभोक्ता कई दिनों तक बिना बिजली के रहे। वहीं, दक्षिणी काउ जिले के कई इलाकों में सड़कों पर कीचड़, बड़े पत्थर और गिरे हुए पेड़ जमा हो जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हवाई पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति की मौत का संबंध संभवत: हरिकेन लाला से था, जबकि एक अन्य मौत भी तूफान से जुड़ी हो सकती है।

रूस-यूक्रेन शांति समझौते में यूरोप की भी होंगी शर्तें: काजा कलास

विल्नियस। यूरोपीय संघ (ईयू) की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने कहा कि यूरोप को अपने हितों का भी ध्यान रखना होगा। रूस और यूक्रेन के बीच भविष्य में होने वाले किसी भी शांति समझौते में यूरोप की तरफ से भी कुछ प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी। कलास ने यह बात सोमवार को लिथुआनिया के दौरे के दौरान कही। इससे पहले सप्ताहांत में अमेरिका के वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने रूस और यूक्रेन का दौरा किया था। उनका उद्देश्य युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाना था। लिथुआनिया के प्रधानमंत्री मिंडाउगास सिंकिविसियस के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलास से पूछा गया कि क्या सप्ताहांत की बातचीत से शांति की संभावना बढ़ी है और अगर किसी संभावित त्रिपक्षीय शिखर बैठक में यूरोपीय संघ को जगह नहीं मिली, तो क्या इससे यूरोप की भूमिका कमजोर हो जाएगी। इस पर कलास ने कहा कि आखिरकार रूस और यूक्रेन को सीधे एक-दूसरे से बात करनी होगी।

उन्होंने कहा, 'यूरोप की तरफ से यह साफ है कि हम रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ नहीं बन सकते। दोनों देशों को आपस में बातचीत करनी होगी। हम हमेशा यूक्रेन के पक्ष में रहे हैं, इसलिए इस मामले में हम तटस्थ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी अंतिम शांति समझौते में 'यूरोप से बहुत सी मांगें' शामिल होंगी, और ऐसी चीजें यूरोप को 'बिना कुछ पाए' नहीं देनी चाहिए। सोमवार को ही कलास ने लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानास नौसेदा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूरोपीय संघ की परिषद की आगामी अध्यक्षता के दौरान लिथुआनिया की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। नौसेदा ने कहा कि अपनी अध्यक्षता के दौरान लिथुआनिया यूरोप की सुरक्षा और रक्षा, यूरोपीय संघ के विस्तार, प्रतिस्पर्धात्मकता, आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक मजबूती जैसे मुद्दों पर खास ध्यान देगा। इस बीच, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को क्रेमलिन में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की। यह बैठक तीन घंटे से ज्यादा चली। इसके बाद रविवार को विटकॉफ और कुशनर ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। इसके अलावा, इससे पहले यूक्रेन, अमेरिका और रूस के प्रतिनिधिमंडलों के बीच अबू धाबी में 23-24 जनवरी और 4-5 फरवरी को दो दौर की बातचीत हुई थी। इसके बाद 17-18 फरवरी को जिनेवा में एक और दौर की वार्ता हुई। इन बैठकों का उद्देश्य रूस-यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने का रास्ता तलाशना था।

यमन के अल-जौफ में जेल पर हवाई हमला, कई कैदी मलबे में फंसे

सना,एजेंसी। उत्तरी यमन के हूती नियंत्रण वाले अल-जौफ प्रांत में एक जेल पर हवाई हमला हुआ, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है। हूती संचालित अल-मसीरा टीवी ने इस हमले के लिए सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह हमला सोमवार को प्रांत की राजधानी अल-हजम में स्थित जेल पर हुआ। इसमें महिलाओं और बच्चों के भी हताहत होने की बात कही गई है। अल-मसीरा ने जेल निदेशक के हवाले से बताया कि 35 कैदी और अपने पति से मिलने आई एक महिला अब भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं।

टीवी चैनल की ओर से दिखाए गए वीडियो में जेल को भारी नुकसान पहुंचा हुआ दिखाई दिया। साथ ही बचावकर्मी मलबे में फंसे लोगों की तलाश करते नजर आए। सि?न्हुआ समाचार एजेंसी ने अल-मसीराह टीवी के हवाले से बताया कि इस मामले पर सऊदी अरब की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इस बीच, हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारिया ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्सा' पर कहा कि यमन में सऊदी सैन्य कार्रवाइयों का 'जवाब दिया जाएगा।' उन्होंने आरोप लगाया कि इन कार्रवाइयों में हवाई हमले, निगरानी उड़ानें और यमनी सरकारी बलों को हथियारों की आपूर्ति शामिल है। यमन साल 2014 के अंत से संघर्ष की चपेट में है। उस समय हूती लड़ाकों ने राजधानी सना और उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 2015 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार के समर्थन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हस्तक्षेप किया था। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में अप्रैल 2022 में एक युद्धविराम लागू हुआ था, लेकिन छह महीने बाद इसकी अवधि समाप्त हो गई और इसे औपचारिक रूप से आगे नहीं बढ़ाया गया। हालांकि हाल के तनाव बढ़ने तक एक नाजुक और अनौपचारिक युद्धविराम काफी हद तक बना रहा। हूती समूह ने जुलाई में सऊदी अरब से जुड़े समुद्री जहाजों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद उसने सऊदी तेल टैंकरों और तेल सुविधाओं पर हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। इसी बीच, यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैंस ग्रंडबर्ग ने कहा है कि हाल ही में विभिन्न मोर्चों पर हुए हूती हमले 'बेहद चिंताजनक घटनाक्रम' हैं, जो संघर्ष को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सोमवार को 'एक्स ' पर जारी एक बयान में ग्रंडबर्ग ने कहा कि आम नागरिकों के मारे जाने और घायल होने, परिवारों के विस्थापित होने तथा नागरिक ढांचे को नुकसान पहुंचने की खबरें 'गहरी चिंता पैदा करने वाली' हैं। उन्होंने कहा कि अगर फिर से बड़े पैमाने पर लगातार लड़ाई शुरू होती है, तो इसका खामियाजा सबसे ज्यादा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। साथ ही राजनीतिक समाधान तक पहुंचने का रास्ता, जो पहले से ही मुश्किल है, और कठिन हो जाएगा। ग्रंडबर्ग ने सभी पक्षों से अपील की कि वे 'हर तरह की लड़ाई और हिंसा रोकें', अधिकतम संयम बरतें और तनाव बढ़ने से रोकने के लिए मौजूद संवाद तंत्र का इस्तेमाल करें। इनमें संयुक्त राष्ट्र की मिलिट्री कोऑर्डिनेशन कमेटी भी शामिल है।

मजदूर दिवस घोषणापत्र में ट्रंप ने एच-1बी फीस का किया समर्थन

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लेबर डे घोषणापत्र में एच-1बी वीजा याचिकाओं पर नई फीस लगाने के प्रस्ताव को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी कंपनियां विदेश से टैलेंट लाने से पहले अमेरिकी वर्कर्स में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने घोषणापत्र में कहा, 'यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम अमेरिकी वर्कर्स को नियुक्त और ट्रेन कर रहे हैं, हम एच-1बी वीजा याचिकाओं पर एक नई फीस का प्रस्ताव कर रहे हैं जो कंपनियों को विदेश में लेबर देखने से पहले योग्य अमेरिकियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

राष्ट्रपति ट्रंप के इस समर्थन के साथ राजनीतिक रूप से संवेदनशील एच-1बी वीजा प्रोग्राम सीधे ट्रंप के लेबर डे संदेश में आ गया, जिसमें मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, टैरिफ और अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा पर जोर दिया गया था। एच-1बी प्रोग्राम का इस्तेमाल अमेरिका की टेक कंपनियां और अन्य नियोक्ता बड़ी संख्या में करते हैं ताकि वे विदेशी कुशल प्रोफेशनल्स को हायर कर सकें। भारतीय नागरिक ऐतिहासिक रूप से एच-1बी लाभार्थियों का सबसे बड़ा समूह रहे हैं, इसलिए इस प्रोग्राम में किसी भी बदलाव पर भारत और अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल समुदाय की बारीकी से नजर रहती है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने पिछले महीने सभी एच-1बी याचिकाओं के लिए 1,03,265 डॉलर की फीस तय करने का प्रस्ताव रखा था, जो सालाना संख्यात्मक सीमा के अधीन हैं, जिनमें एडवांस्ड-डिग्री छूट के लिए योग्य याचिकाएं भी शामिल हैं।

प्रस्तावित नियम के तहत यह फीस याचिका दायर करते समय देनी होगी और यह अन्य लागू इमिग्रेशन फीस के अलावा होगी। प्रशासन का कहना है कि यह पैसा कानूनी इमिग्रेशन सिस्टम को चलाने से जुड़ी संघीय लागतों को कवर करने में मदद करेगा। ट्रंप ने एच-1बी प्रस्ताव को अमेरिकी वर्कर्स को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से बनाई गई एक व्यापक आर्थिक रणनीति के हिस्से के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा, 'दशकों की खराब व्यापार नीतियों के बाद, जिन्होंने हमारी औद्योगिक ताकत को विदेशी देशों के हवाले कर दिया था, कंपनियां अब घर लौट रही हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ट्रिलियन डॉलर का निवेश कर रही हैं और 9 लाख से ज्यादा अमेरिकी नौकरियां जोड़ रही हैं।

ऑस्ट्रेलिया: सोशल मीडिया यूजर्स को मिलेगा 'एल्गोरिदम से आजादी का विकल्प', उल्लंघन पर 100 मिलियन डॉलर तक जुर्माना

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया यूजर्स को जल्द यह तय करने का अधिकार मिल सकता है कि वे प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम से सुझाई सामग्री देखना चाहते हैं या सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स की पोस्ट देखना चाहते हैं, जिन्हें वे खुद फॉलो करते हैं। इसका ऐलान प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मंगलवार को किया। अल्बनीज ने मंगलवार को संसद भवन में पत्रकारों से बातचीत में प्रस्तावित 'डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर कानून' की घोषणा की। इसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को 16 वर्ष से अधिक उम्र के यूजर्स को एल्गोरिदम आधारित फीड से बाहर निकलने का विकल्प देना होगा।

अल्बनीज ने कहा कि इसका मकसद ऑनलाइन दुनिया में लोगों को ज्यादा नियंत्रण और विकल्प देना है। उन्होंने कहा, 'यह लोगों को नियंत्रण देने के बारे में है। यह ऑनलाइन ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के हाथों में विकल्प वापस देने के बारे में है। संचार मंत्री अनिका वेल्स ने कहा कि नए कानून के तहत प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि 18 वर्ष से कम उम्र के यूजर्स को ऐसे हानिकारक कंटेंट से सुरक्षा मिले, जिसमें 'ईटिंग डिसऑर्डर को बढ़ावा देने वाली सामग्री, महिलाओं के प्रति घृणा या पुरुषवादी सोच को बढ़ावा देने वाला कंटेंट और अपराध का महिमामंडन' शामिल है। नए नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 10 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 7.21 करोड़ अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। वेल्स के अनुसार, '16 वर्ष से अधिक उम्र के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक आसानी से एल्गोरिदम को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेंगे। जब यूजर कोई सोशल मीडिया ऐप खोलेगा, तो प्लेटफॉर्म को उसे यह विकल्प देना होगा कि वह किस तरह की फीड देखना चाहता है और यूजर की पसंद का सम्मान करना होगा।' उन्होंने तकनीकी कंपनियों पर निशाना साधते हुए कहा, 'लंबे समय से ये कंपनियां ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों पर वास्तविक समय में बिना पर्याप्त नियमन के अपने उत्पादों का परीक्षण करती रही हैं और उनके प्लेटफॉर्म लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह घुस गए हैं, जिसकी कल्पना पहले नहीं की गई थी। वेल्स ने कहा, 'बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जवाबदेही का दौर आने वाला है।

सऊदी अरब दौरे पर कीर्ति वर्धन सिंह: भारतीय समुदाय से की मुलाकात, कहा- आपका योगदान अमूल्य

रियाद,एजेंसी। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय के एक बड़े वर्ग के साथ संवाद किया और प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने में उनकी भूमिका की सराहना की। सिंह ने समुदाय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के विजन को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाने का भी आग्रह किया।

मंगलवार को एक्स पोस्ट में, राज्य मंत्री (एमओएस) ने कहा, 'दूतावास के संरक्षण में 'ऑल-इंडिया स्टीयरिंग कमेटी' द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सऊदी अरब में जीवंत भारतीय समुदाय के विभिन्न लोगों से मिलकर खुशी हुई। व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्रों में भारत-सऊदी अरब संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान सराहनीय है। उन्हें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत2047' के विजन को साकार करने में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। सिंह ने रियाद में 'इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एलुमनाई चैप्टर - सऊदी अरब' का भी उद्घाटन किया और कहा, 'उन पूर्व छात्रों से मिलकर अच्छा लगा जिन्होंने इस देश को अपना दूसरा घर बना लिया है और जो अपने शिक्षण संस्थान (अल्मा मेटर) के मूल्यों और सीख को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सोमवार को, सिंह ने भारतीय व्यापारियों, उद्यमियों, निवेशकों और पेशेवरों के साथ भी संवाद किया और सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनकी 'अमूल्य' भूमिका की सराहना की। राज्य मंत्री सिंह ने इसकी जानकारी भी एक्स पर दी। उन्होंने

कहा, 'सऊदी अरब में भारतीय व्यापारियों, उद्यमियों, निवेशकों और पेशेवरों के साथ सार्थक बातचीत हुई। भारत-सऊदी अरब द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनकी अमूल्य भूमिका की सराहना की और दोनों देशों के बीच व्यापार के अवसरों का लाभ उठाने पर चर्चा की, जिसमें 3टी - व्यापार (ट्रेड), निवेश (इंवेस्टमेंट), पर्यटन (टूरिज्म) और प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) में साझेदारी को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने रियाद में भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ बातचीत की और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के 3टी—व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन—के विजन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। राज्य मंत्री सिंह ने कहा, 'भारत-सऊदी अरब संबंधों को और मजबूत करने तथा प्रभावी, नागरिक-केंद्रित कांसुलर सेवाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत दूतावास में एक पौधा भी लगाया। सिंह ने एक्स पर कहा, 'एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रियाद में भारतीय दूतावास में अपनी मां को समर्पित एक पौधा लगाया - यह पहल मातृत्व के प्रति हमारे गहरे सम्मान और हरित भविष्य के प्रति हमारी साझा जिम्मेदारी को खूबसूरती से दर्शाती है।'

उरुग्वे को मिला भारत का पहला रेजिडेंट एंबेसडर, राजदूत बिनय जॉर्ज ने राष्ट्रपति को सौंपा परिचय पत्र

मोंटेवीडियो,एजेंसी। ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे को भारत का पहला रेजिडेंट एंबेसडर मिल गया है। भव्य समारोह में बिनय बिनॉय जॉर्ज ने राष्ट्रपति यामान्डु ओर्सी को अपना परिचय पत्र सौंपा। मंगलवार को समारोह की तस्वीरें और वीडियो राष्ट्रपति कार्यालय ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से साझा की। इंस्टाग्राम रील्स में बिनय जॉर्ज को अपने क्रेडेंशियल्स (लेटर ऑफ क्रेडेंस) सौंपते हुए देखा जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'हमने उरुग्वे और भारत के रिश्तों में एक अहम कदम उठाया है। पहली बार, भारत के एक रेजिडेंट एंबेसडर हमारे देश में आए हैं। हमने बिनॉय जॉर्ज के क्रेडेंशियल्स स्वीकार किए और ऐसे रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू किया जिनमें बहुत संभावनाएं हैं।

उन्होंने आगे लिखा, 'भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश और एक बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी है। उरुग्वे के पास व्यापार बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और हमारे समाजों के बीच संबंधों को मजबूत करने के काफी मौके हैं। संभावनाओं के खुलते द्वार का जिक्र करते हुए आगे कहा, 'दुनिया के साथ जुड़ने से हमारे प्रोडक्शन, हमारे बिजनेस और हमारे लोगों के लिए और ज्यादा मौके बनते हैं। दरवाजे खोलना, भरोसा बनाना और देशों को एक-दूसरे के करीब लाना, उरुग्वे के विकास के लिए काम करने जैसा है। हम आगे बढ़ते रहेंगे।

दक्षिण अमेरिका के दूसरे सबसे छोटे देश उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में इसी साल भारत ने रेजिडेंट दूतावास खोला है। अगस्त 2026 में मोंटेवीडियो में भारतीय दूतावास ने अपना काम शुरू किया। इससे पहले अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स स्थित भारतीय दूतावास से ही उरुग्वे के कामकाज को संभाला जाता था। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1948 (आधिकारिक मान्यता 1960) में स्थापित हुए थे। बता दें कि लेटर ऑफ क्रेडेंस एक औपचारिक दस्तावेज होता है जो किसी भी राजनयिक की दूसरे संप्रभु राज्य में राजदूत या उच्चायुक्त नियुक्त होने की पहचान होता है। वो इसके जरिए अपना परिचय प्रस्तुत करते हैं। कूटनीतिक भाषा में इस कार्यक्रम को ही क्रेडेंशियल सेरेमनी कहा जाता है।

एफिल टॉवर विवाद पर बीएपीएस ने मांगी माफी, कहा- किसी को प्रवेश से नहीं रोका गया

पेरिस,एजेंसी। पेरिस स्थित बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) हिंदू मंदिर ने स्पष्ट किया है कि एफिल टॉवर पर मंदिर के प्रतिनिधिमंडल की निजी यात्रा स्मारक प्रबंधन के साथ मिलकर तय की गई थी। इसे आम खुलने के समय के ठीक पहले रखा गया था ताकि दूसरे पर्यटकों को कम से कम असुविधा हो। बीएपीएस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्सधर' पर जारी एक बयान में कहा कि किसी भी व्यक्ति को एफिल टॉवर में प्रवेश से नहीं रोका गया था। बीएपीएस ने उन लोगों से माफी भी मांगी जिन्हें इस घटना से कोई ठेस पहुंची हो या असुविधा हुई हो।

यह स्पष्टीकरण एफिल टॉवर के कर्मचारियों की हड़ताल के बाद आया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया था कि प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान महिला कर्मचारियों को परिसर से हटाया गया था। यह विवाद पिछले सप्ताह बीएपीएस से जुड़े लगभग 100 लोगों के एक निजी दौरे से जुड़ा था, जो पेरिस के बाहरी इलाके में एक मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए फ्रांस आए थे। मंदिर की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'हम उठाई गई चिंताओं का सम्मान करते हैं और उन्हें बहुत गंभीरता से लेते हैं। हमारे प्रतिनिधिमंडल का आकार बड़ा था, इसलिए इस यात्रा की व्यवस्था एफिल टॉवर प्रबंधन के सहयोग से सामान्य समय पर खुलने के ठीक शुरुआत में की गई थी, ताकि अन्य लोगों को कोई असुविधा या व्यवधान न हो। हमारी जानकारी के अनुसार, किसी भी समय किसी को एफिल टॉवर में प्रवेश से नहीं रोका गया। फिर भी, अगर किसी को दुख पहुंचा है या किसी प्रकार की असुविधा हुई है, तो हम इसके लिए दिल से माफी मांगते हैं। हम आपसी सम्मान और सेवा जैसे सार्वभौमिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं।' पेरिस के मेयर इमैनुएल ग्रेगोइरे ने कहा कि इस मामले की जांच जितनी जल्दी संभव हो सके शुरू की जाएगी। उन्होंने 'एक्स ' पर एक पोस्ट में कहा, 'मैं एफिल टॉवर के कर्मचारियों की ओर से जताए गए गुस्से को समझता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि उनकी नाराजगी जायज है। उन्होंने लिखा, 'यह बेहद जरूरी है कि उन सभी तथ्यों को सामने लाया जाए, जिनकी वजह से यह विरोध प्रदर्शन हुआ। फ्रांस की समानता मामलों की मंत्री ऑरोर बर्गे ने भी 'एक्सथ' पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'फ्रांस में हम महिलाओं से खुद को पीछे हटाने या अदृश्य होने के लिए नहीं कहते। कोई भी विचारधारा या धर्म गणराज्य के कानूनों से ऊपर नहीं है। इस घटना की आलोचना करते हुए दक्षिणपंथी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मरीन ले पेन ने कहा कि फ्रांस कभी भी महिलाओं की मौजूदगी को 'सीमित' किए जाने को स्वीकार नहीं करेगा। हर साल करीब 70 लाख पर्यटकों को आकर्षित करने वाला एफिल टॉवर सोमवार को पूरे दिन बंद रहा। हालांकि कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि के अनुसार, इसे मंगलवार को सामान्य रूप से फिर से खोल दिया जाएगा।

एक नजर

कुंभ-2027 से पहले उत्तराखंड को 8,029 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न, मुख्यमंत्री धामी ने जताया आभार

देहरादून,एजेंसी। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेला-2027 की तैयारियों के बीच केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 8,029.152 मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं और चावल आवंटित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कुंभ को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और भव्य बनाने के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार उत्तराखंड को 3,051.079 मीट्रिक टन गेहूं और 4,978.073 मीट्रिक टन चावल अतिरिक्त रूप से दिया गया है। यह आवंटन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बड़े धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुंभ जैसे बड़े आयोजनों के लिए संबंधित राज्य को उसके वार्षिक खाद्यान्न आवंटन का अधिकतम दो प्रतिशत तक अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किया जा सकता है। इसी व्यवस्था के तहत उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुंभ मेला-2027 को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और भव्य रूप से आयोजित करने के लिए राज्य सरकार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है। सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए राज्य सरकार की ओर से खाद्य आपूर्ति समेत यातायात, पेयजल, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन को इन तैयारियों की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है।

पेयजल आपूर्ति के दौरान पाइप बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों को ठीक किया जाएगा : स्वतंत्र देव सिंह

लखनऊ। योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल आपूर्ति के साथ लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा देने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मानसून के बाद अक्टूबर से पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर सड़क की मरम्मत का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को अभियान से जुड़ी सभी तैयारियां समय से पूरी करने को कहा है, ताकि पेयजल योजनाओं के लिए खोदी गई सड़कों को जल्द दुरुस्त कर ग्रामीणों को राहत दी जा सके। जलशक्ति मंत्री ने राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न पेयजल योजनाओं की मंडलवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने के दौरान कई स्थानों पर सड़कें खोदी गई हैं। मानसून के दौरान बारिश के कारण इन मार्गों पर लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अक्टूबर से अभियान चलाकर इन सड़कों को दोबारा भरकर, समतल करते हुए दुरुस्त किया जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं का काम पूरा होने के साथ लोगों को बेहतर सड़क सुविधा भी मिल सकेगी। पेयजल योजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देशनिर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय में जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए जरूरत के अनुसार मैनपावर बढ़ाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

'आपको न्याय मिलेगा', गौरव गोगोई ने मणिपुर के म्यूजिशियन की हत्या पर जाहिर किया दुख

गुवाहाटी,एजेंसी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने मंगलवार को मणिपुर के म्यूजिशियन चोंगथम विक्रम सिंह की मृत्यु पर दुख जाहिर किया। विक्रम सिंह ने दक्षिण दिल्ली स्थित अपने आवास के बाहर तेज आवाज में म्यूजिक चलाने पर आपत्ति जताई, तो कथित तौर उन्हें पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। गोगोई ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट करके सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पूरा पूर्वोत्तर भारत दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा है।

सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए गोगोई ने अपने पोस्ट में लिखा, 'चोंगथम विक्रम सिंह एक विनम्र व्यक्ति थे। उनमें कोई अहंकार नहीं था, उनका किसी के साथ बैर भी नहीं था। वह एक शांतिप्रिय व्यक्ति थे, जो सिर्फ संगीत से प्रेम करते थे। उन्हें हर कोई पसंद करता था। गोगोई ने कहा, 'दिवंगत आत्मा को शांति मिले। आपको न्याय मिलेगा। पूरा पूर्वोत्तर भारत आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सिंह ने दक्षिण दिल्ली स्थित अपने आवास के बाहर तेज शोर पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद उन्हें पीटा गया, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। कांग्रेस नेता की टिप्पणी ने सिंह के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए संगीत के क्षेत्र में दिए उनके योगदान को भी सराहा। गोगोई ने उन्हें एक शांतिपूर्ण व्यक्ति बताया और कहा कि वो बैर-भाव से दूर रहते थे और सिर्फ कला के लिए जीते थे। इस हादसे के बाद मणिपुर समुदाय के साथ पूरे पूर्वोत्तर भारत के लोगों में शोक है। लोग म्यूजिशियन के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की सही से जांच होनी चाहिए, ताकि यह साफ हो सके कि आखिर किन परिस्थितियों में म्यूजिशियन की मौत हुई थी? पुलिस अब अपनी जांच के तहत यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हमले के पीछे पूरा घटनाक्रम क्या रहा है। इसमें सिंह के घर के बाहर संगीत को लेकर विवाद भी शामिल है। पुलिस अब यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो लोग भी इस हमले में शामिल थे, उनकी भूमिका क्या थी? इस हादसे के बाद से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ रही है। लोग सिंह के परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और इस मामले में जवाबदेही भी तय करने की मांग कर रहे हैं। वहीं, इस मामले में जांच के संबंध में अतिरिक्त जानकारियों का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करना शामिल है।

बरसात में बढ़ा जल-मच्छर जनित बीमारियों का खतरा, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

देहरादून,एजेंसी। बरसात के मौसम में जल जनित और मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। डायरिया, टायफायड, हैजा, पीलिया, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (आईडीएसपी) के माध्यम से प्राप्त साप्ताहिक रिपोर्टों के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग ने खान-पान और स्वच्छता को लेकर जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग ने जनसामान्य से बासी भोजन का सेवन न करने तथा बाजार में खुले में बिक रहे खाद्य पदार्थों एवं अधपके भोजन से बचने की अपील की है। विभाग ने सलाह दी है कि घर में पानी को अच्छी तरह उबालकर रखें और पीने तथा खाना बनाने में इसी का प्रयोग करें। पानी को क्लोरीनयुक्त करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का प्रयोग स्वास्थ्य कर्मियों के निर्देशानुसार ही किया जाए। शौचालय के उपयोग के बाद तथा भोजन करने से पहले साबुन से हाथ धोने की आदत अपनाएं। फलों एवं सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही सेवन करें।

स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया से बचाव के लिए लोगों से अपने घरों एवं आसपास पानी एकत्रित न होने देने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि सभी पानी की टंकियों एवं जल भंडारण के बर्तनों को ढककर रखें। घरों में लगे गमलों के नीचे पानी एकत्रित करने वाली ट्रे न लगाएं और गमलों में पानी जमा न होने दें। फ्रिज के पीछे, कूलर, गुलदस्तों, मनी प्लांट, पानी के बर्तनों सहित ऐसे सभी स्थानों की नियमित रूप से सफाई करें, जहां पानी जमा हो सकता है। इन वस्तुओं का पानी सप्ताह में कम से कम एक बार पूरी तरह खाली कर उन्हें सुखाकर ही दोबारा उपयोग करें। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से पुराने टूटे बर्तन, बोतल, डिब्बे, बेकार टायर आदि खुले में न फेंकने की अपील की है। इनमें जमा होने वाला पानी डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर के प्रजनन का कारण बन सकता है। मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करने, आवश्यकता के अनुसार मच्छररोधी साधनों का उपयोग करने तथा ऐसे कपड़े पहनने की सलाह दी गई है, जिससे शरीर का अधिक से अधिक हिस्सा ढका रहे। बच्चों एवं आमजन को मच्छर जनित रोगों से बचाव के संबंध में जागरूक करना भी आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि तेज बुखार, सिरदर्द, बदन एवं मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द तथा शरीर पर लाल चकत्ते जैसे लक्षण दिखाई देने पर इसे नजरअंदाज न करें और तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लें।

भदई अमावस्या स्नान पर्व को लेकर बांदा में यातायात व्यवस्था कड़ी, पैदल श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात में किया बदलाव

बांदा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भाद्रपद अमावस्या (भदई अमावस्या) स्नान पर्व के अवसर पर 10 व 11 सितम्बर को उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश में बांदा जनपद पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की है। बांदा से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल और वाहनों से चित्रकूट की ओर रवाना होंगे। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यातायात में बदलाव करते हुए कई मार्गों पर भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया है। भक्तों की सफल और सुरक्षित यात्रा को लेकर मंगलवार से ही ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने भदई अमावस्या को देखते हुए जनपद की यातायात व्यवस्था का आज शुभ निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न डायवर्जन प्वाइंटों और मार्गों का स्थलीय जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यातायात पुलिस और संबंधित पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के साथ ही डायवर्जन व्यवस्था का प्रभावी ढंग से पालन करने के मातहत पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए। यातायात व्यवस्था के तहत बांदा से चित्रकूट जाने वाले भारी वाहनों पर अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे वाहन बिसंडा-पहाड़ी मार्ग अथवा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं कबरई तिराहा, महोबा से मटौंध-बांदा-खुरहंड-अतर्रा-बदौसा एनएच-35 मार्ग पर भारी वाहनों का दिन-रात आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। भारी वाहन कबरई तिराहा से खन्ना होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के रास्ते आवागमन कर सकेंगे। पुलिस के अनुसार बांदा-बेदा घाट, बांदा-चिल्ला तथा बांदा-नरैनी-कालिंजर मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन सामान्य रहेगा। वहीं 08 और 09 सितंबर को बांदा-खुरहंड-अतर्रा-बदौसा-चित्रकूट मार्ग पर भारी वाहनों के साथ बसों और चार पहिया वाहनों के आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगा। चित्रकूट जाने वाले चार पहिया वाहन बिसंडा-पहाड़ी मार्ग अथवा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का प्रयोग करेंगे। पैदल चित्रकूट जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बांदा-खुरहंड-अतर्रा-बदौसा-चित्रकूट मार्ग निर्धारित किया गया है। पुलिस ने श्रद्धालुओं से बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे अथवा अन्य वैकल्पिक मार्गों पर पैदल न चलने की अपील की है। साथ ही श्रद्धालुओं के पैदल यात्रा मार्ग पर भारी वाहन, बस और चार पहिया वाहन न ले जाने की भी अपील की गई है। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में यातायात व्यवस्था बाधित न होने पाए और श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ने में सहयोग किया जाए।

पंजाब में ड्रग्स संकट पर अमित मालवीय का हमला, बोले- सवाल उठाने वालों को डराती है सरकार

चंडीगढ़,एजेंसी। भाजपा नेता अमित मालवीय ने पंजाब में ड्रग्स की समस्या को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। यह आलोचना संगरूर के एक व्यक्ति की मौत के बाद शुरू हुए राजनीतिक हंगामे के बीच की गई है। इस व्यक्ति ने राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के सामने सार्वजनिक रूप से हेरोइन की आसानी से उपलब्धता का मुद्दा उठाया था। इस घटना ने एक बार फिर ड्रग्स के संकट को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। विपक्षी पार्टियां मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार के बहुत ज्यादा प्रचारित ड्रग विरोधी अभियान की प्रभावशीलता पर सवाल उठा रही हैं। संगरूर जिले के रहने वाले गुलजार सिंह ने जहर खा लिया था। उन्होंने दावा किया था कि अपने गांव में चिट्टा (एक तरह का नशीला पदार्थ) के प्रसार को लेकर चीमा से सार्वजनिक रूप से सवाल पूछने के बाद उन पर दबाव डाला गया था। उनकी मौत ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। विपक्ष सरकार पर ड्रग की लत से प्रभावित परिवारों की चिंताओं को दूर करने में विफल रहने का आरोप लगा रहा है।

भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि इस घटना ने पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ने के सरकार के दावों के पीछे की कड़वी सच्चाई को उजागर कर दिया है। उन्होंने मान सरकार पर युवाओं के बीच नशीले पदार्थों को फैलाने के लिए जिम्मेदार सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से निपटने के बजाय प्रचार को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। हालांकि, आप सरकार का कहना है कि उसके 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के कारण ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है और ड्रग नेटवर्क को तोड़ा गया है। आप सरकार

ने केंद्र पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की सीमा-पार तस्करी को रोकने में विफल रहने का भी बार-बार आरोप लगाया है। मालवीय ने एक्स पर लिखा कि दिर्बा निर्वाचन क्षेत्र के टूर बंजारा गांव के निवासी गुलजार सिंह ने आप मंत्री हरपाल सिंह चीमा से उनके दौरे के दौरान 'चिट्टा' की बेरोकटोक बिक्री के बारे में सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि उनका अपना बेटा नशे की लत से जूझ रहा है और उसने परिवार का सामान बेच दिया है।

इसके बाद आप से जुड़े स्थानीय नेताओं ने उन पर दबाव डाला और उन्हें परेशान किया। उन्होंने मांग की कि गुलजार सिंह मंत्री से सवाल पूछने के लिए माफी मांगें। उन्होंने इनकार कर दिया। जहर खाने से पहले रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में गुलजार सिंह ने अपनी दुर्दशा के लिए चार लोगों को जिम्मेदार ठहराया, जिनमें हरपाल चीमा और स्थानीय गांव के नेता शामिल थे। बाद में इलाज के बावजूद उनकी मौत हो गई। मालवीय ने दावा किया कि यह बेहद परेशान करने वाला है। जो सरकार ड्रग्स की समस्या पर सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकती और सवाल उठाने वाले नागरिक को डराती-धमकाती है, उसे जवाब देना होगा। पंजाब जवाबदेही का हकदार है, डराने-धमकाने का नहीं। इस बीच, संगरूर के एक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस ने एक सरपंच और दो अन्य लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और परेशान करने का मामला दर्ज किया है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (पटियाला रेंज) कुलदीप सिंह चहल ने मीडिया को बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया जाएगा, हालांकि पुलिस ने परेशान करने के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं।

दुर्गा मंदिर में तीन दिवसीय संगीत समारोह, मनोज तिवारी भी देंगे प्रस्तुति

वाराणसी,एजेंसी। काशी के प्रसिद्ध दुर्गाकुंड मंदिर में मां दुर्गा के वार्षिक संगीतमय श्रृंगार महोत्सव का शुभारंभ मंगलवार से होने जा रहा है। तीन दिवसीय इस भव्य संगीत समारोह में देश के विभिन्न हिस्सों से आए ख्यातिलब्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ, लोकगायक और नृत्य कलाकार मां दुर्गा के चरणों में अपनी कला अर्पित करेंगे। धार्मिक आस्था और भारतीय संगीत परंपरा के संगम से सजे इस आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महोत्सव के दौरान तीनों दिन अलग-अलग रंग और शैली के संगीत एवं नृत्य की प्रस्तुतियां होंगी। मंदिर परिसर में होने वाले कार्यक्रम में शास्त्रीय वादन से लेकर भक्ति संगीत और लोकगायन तक की प्रस्तुतियां श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति कराएंगी।

शहनाई वादन से होगा आगाज

महोत्सव के पहले दिन मंगलवार को कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक वादन और शास्त्रीय संगीत से होगी। प्रसिद्ध शहनाई वादक पं. जवाहर लाल अपनी शहनाई की मधुर धुनों से कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद पद्मश्री पं. शिवनाथ और पं. देवव्रत सितार की जुगलबंदी प्रस्तुत करेंगे। सितार की जुगलबंदी समारोह के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहेगी। वहीं, प्रसिद्ध बांसुरी वादक पं. राजेंद्र प्रसन्ना का बांसुरी वादन भी श्रोताओं के लिए विशेष आकर्षण रहेगा। बांसुरी की मधुर तान और शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियों से मंदिर परिसर का वातावरण भक्तिमय होने की उम्मीद है। इसके अलावा कथक नृत्य और शास्त्रीय गायन की प्रस्तुतियां भी पहले दिन कार्यक्रम को विविधता प्रदान करेंगी।

दूसरे दिन बहेगी भक्ति संगीत की धारा

महोत्सव के दूसरे दिन बुधवार को शाम चार बजे से देर रात तक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दिनभर चलने वाली प्रस्तुतियों के दौरान श्रद्धालु भजन और लोक संगीत का आनंद ले सकेंगे। महाआरती के बाद प्रसिद्ध लोकगायक अरविंद अकेला 'कल्लू' भजनों की प्रस्तुति देंगे। कल्लू की प्रस्तुति को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह है। महाआरती के बाद भक्ति संगीत के बीच लोकगायन का यह कार्यक्रम धार्मिक वातावरण को और अधिक जीवंत बनाएगा।

भरतनाट्यम और भजन संध्या से होगा समापन

महोत्सव के अंतिम दिन बृहस्पतिवार को भी संगीत और नृत्य की विविध प्रस्तुतियां होंगी। समापन दिवस पर भरतनाट्यम, शास्त्रीय संगीत और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति के साथ संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। समापन समारोह का प्रमुख आकर्षण गायक एवं सांसद मनोज तिवारी मृदुल की गायकी होगी। वह अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से श्रद्धालुओं और संगीत प्रेमियों को भक्ति रस में सराबोर करेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर भी आयोजन से जुड़े लोगों में उत्साह है।

मां के श्रृंगार के साथ संगीत की आराधना

दुर्गाकुंड मंदिर में आयोजित होने वाला यह वार्षिक संगीतमय श्रृंगार महोत्सव केवल मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि संगीत को मां दुर्गा के चरणों में समर्पित करने की परंपरा से जुड़ा आयोजन है। तीन दिनों तक मंदिर परिसर में शास्त्रीय संगीत, लोकगायन और नृत्य की प्रस्तुतियों के माध्यम से कलाकार अपनी साधना मां को अर्पित करेंगे। काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में संगीत का विशेष स्थान रहा है। ऐसे में दुर्गाकुंड मंदिर का यह आयोजन श्रद्धालुओं के साथ-साथ संगीत प्रेमियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। अलग-अलग विधाओं के कलाकारों की मौजूदगी से समारोह में भारतीय संस्कृति की विविध छटा देखने को मिलेगी।

आयोजन की जिम्मेदारी

तीन दिवसीय संगीतमय श्रृंगार महोत्सव का संयोजन विश्वेश्वर झा (सोनू महाराज) कर रहे हैं। आयोजन के मुख्य आयोजक बिंदु दूबे और मानसी दूबे हैं, जबकि कार्यक्रम का संचालन प्रभुनाथ राय करेंगे। आयोजकों के अनुसार, महोत्सव को धार्मिक गरिमा और सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप भव्य रूप देने की तैयारी की गई है। तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में मां दुर्गा के दरबार में सुर, ताल, नृत्य और भक्ति का संगम देखने को मिलेगा। काशी के श्रद्धालुओं और संगीत प्रेमियों के लिए यह महोत्सव आध्यात्मिक आनंद के साथ भारतीय संगीत परंपरा से जुड़ने का विशेष अवसर साबित होगा।

जनविरोधी नीतियों के खिलाफ बुलंद आवाज उठाएं कांग्रेस कार्यकर्ता : कुमारी शैलजा

देहरादून। कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी शैलजा ने देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं से भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के बीच जाकर आवाज उठाने का आह्वान किया है। कुमारी शैलजा ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के विभिन्न फ्रंटल संगठनों, विभागों एवं प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने पदाधिकारियों को शीघ्र कार्यकारिणी गठित करने और प्रदेशभर में व्यापक दौरे कर संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए। शैलजा ने कहा कि जनता भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान है। दलितों के साथ कथित अन्याय, महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान, बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर मजबूती से आवाज उठानी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर उनके समाधान के लिए संघर्ष करे। इसके बाद कुमारी शैलजा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्षों,

महामंत्रियों और सचिवों की बैठक को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को बुलंद आवाज उठानी होगी। आम जनता, युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं और गरीब वर्ग सरकार की नीतियों से परेशान हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से शीघ्र ही जिलों, महानगरों और विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रभारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर संगठन को एकजुट करने तथा आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि चुनाव केवल नेताओं के प्रयास से नहीं, बल्कि एकजुट और समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीता जाता है। उन्होंने पदाधिकारियों से निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ संगठन के लिए कार्य करने को कहा। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा सरकार की नीतियों और फैसलों का तथ्यात्मक ढंग से विरोध करते हुए जनता की आवाज बने। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव, बूथ और विधानसभा स्तर तक पहुंचकर जनता से संवाद स्थापित करने तथा कांग्रेस की नीतियों एवं विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)